भारत की यात्रा पर आये रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हुई। भारत ने संकेत दिया है कि वह अपने हितों के हिसाब से ही फैसला करेगा।

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:27 अंक: 108 दिनांक: 02-04-2022 शनिवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोयले के दाम में भारी बढोतरी हुई है। यूरोप में कोयले की मांग काफी बढ़ गई है क्योंकि वहां प्राकृतिक गैस की किल्लत हो गई है। इससे आयातित कोयले की सप्लाई प्रभावित हो रही है।

रूसी विदेश मंत्री से मिले पीएम मोदी

हिंसा खत्म करने की अपील, पश्चिमी देशों को संकेत- अपने हितों के हिसाब से ही फैसला करेगा भारत

नई दिल्ली। रूस के साथ अपने रिश्तों को तोड़ने को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से पड़ रहे दबाव के बीच भारत ने शुक्रवार को एक बार फिर अपनी मंशा साफ कर दी है कि वह अपने हितों के हिसाब से ही फैसला करेगा। भारत की यात्रा पर आये रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की पीएम नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अलग-अलग मुलाकात हुई जिसमें यूक्रेन के हालात के साथ ही द्विपक्षीय रिश्तों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हुई।

हाल के दिनों में भारत के दौरे पर आने वाले किसी विदेश मंत्री के साथ पहली बार मोदी ने मुलाकात की है। पीएम मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी इस मुलाकात के दौरान उपस्थित थे। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें यूक्रेन की स्थिति और चल रही शांति वार्ताओं के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने एक बार फिर से यूक्रेन-रूस के बीच हिंसा को समाप्त करने की जरूरत बताई और शांति स्थापित करने के लिए भारत की तरफ से हरसंभव मदद देने की बात कही। लावरोव ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच दिसंबर, 2021 में हुई शिखर सम्मेलन में लिये गये फैसले के बारे में जानकारी दी।

बताते चलें कि पीएम मोदी ने पिछले दो हफ्तों के दौरान भारत के दौरे पर आये ब्रिटेन, ग्रीस, चीन, मैक्सिको व आस्ट्रिया के विदेश मंत्रियों से मुलाकात नहीं की थी। इनमें से कुछ देशों की तरफ से कई बार आग्रह आने के बावजूद पीएम मोदी मिलने का वक्त नहीं निकाल सके थे। इस मुलाकात को उन देशों को दिए गए एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है जो भारत पर दबाव बना रहे हैं कि यूक्रेन पर हमला करने के बारे में रूस के खिलाफ उनके प्रतिबंधों को लागू करने में भागीदार बने और रूस के साथ कूटनीतिक व आर्थिक संबंधों पर रोक लगाये।

अप्रैल, 2021 में लावरोव की भारत यात्रा के दौरान पीएम मोदी से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। तब लावरोव भारत के बाद पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले थे। बताया गया था कि रूसी विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के विरोध में ही पीएम मोदी से लावरोव की मुलाकात नहीं हो सकी थी। मोदी की इस दौरान तीन बार राष्ट्रपति पुतिन से टेलीफोन पर बात हुई है। बहरहाल, यह मुलाकात तब हुई है जब एक दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत पर दबाव बनाने वाले देशों को संकेत दे दिया था कि रूस के साथ रिश्ते भारत अपने हितों के मुताबिक तय करेगा। उन्होंने रूस से इंधन नहीं खरीदने को लेकर ''अभियान'' चलाने वालों को कहा था कि, पश्चिमी देश रूस से ज्यादा तेल खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदते रहेंगे जबकि भारत कभी भी रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले शीर्ष 10 देशों मे शामिल नहीं होगा।

गुरुवार को भारत के दौरे पर आये अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) दलीप उसह ने कहा था कि भारत अगर रूस से ज्यादा ईंधन खरीदता है तो इसके परिणाम भी हो सकते हैं। उन्होंने भारत व रूस के बीच स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने की तैयारियों पर भी निशाना लगया था भारत जैसे मित्र देश को इससे अलग रहने को कहा था। शुक्रवार को जयशंकर से लंबी प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के बाद लावरोव ने बताया कि रूस भारत के साथ स्थानीय मुद्रा में कारोबार बढ़ाने जा रहा है। पहले से ही भारत के साथ स्थानीय मुद्रा (रुपये व रुबल) में कारोबार हो रहा है जो मौजूदा हालात (अमेरिका व पश्चिमी देशों के प्रतिबंध) को देखते हुए और जरूरी हो गया है।

पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से द्विपक्षीय कारोबार पर पड़ने वाले असर के बारे में पूछे जाने पर लावरोव ने कहा कि भारत व रूस के कारोबार व वित्त मंत्रालयों के बीच काफी अच्छे संबंध हैं और मुझे भरोसा है कि पश्चिमि देशों की तरफ से खड़े किये गये गैर कानूनी अवरोधों को तोड़ने का वो कोई विकल्प खोज लेंगे। ऐसा ही सैन्य व तकनीक सहयोग में भी किया जाएगा, उस दिशा में भी संबंधित मंत्रालय काम

मार्च 2022 में कुल जीएसटी संग्रह सबसे ज्यादा, 1,40,986 करोड़ रुपये एकत्र किए

नई दिल्ली (ईएमएस)। मार्च 2022 महीने में एकत्र सकल जीएसटी राजस्व 1,42,095 करोड़ रुपये रहा जिसमें सीजीएसटी 25,830 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 32,378 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 74,470 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 39,131 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 9,417 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 981 करोड़ रुपये सहित) है। मार्च 2022 में कुल सकल जीएसटी संग्रह जनवरी 2022 के महीने में एकत्र किए गए 1,40,986 करोड़ रुपये के पूर्व के रिकॉर्ड को तोड़कर अब तक का सबसे अधिक है। सरकार ने नियमित भुगतान के रूप में आईजीएसटी से 29,816 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 25,032 करोड़ रुपये एसजीएसटी का निपटारा किया। इसके अलावा, केन्द्र ने इस महीने में केन्द्र और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 50:50 के अनुपात में तदर्थ आधार पर आईजीएसटी के 20,000 करोड़ रुपये का निपटारा किया है। मार्च 2022 के महीने में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व नियमित और तदर्थ निपटान के बाद सीजीएसटी के लिए 65646 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 67410 करोड़ रुपये है। केन्द्र ने महीने के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 18,252 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा भी जारी किया।

सीजेआई एनवी रमना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की कार्रवाई और निष्क्रियता पर सवाल उठाये

नई दिल्ली (ईएमएस)। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाई और निष्क्रियता पर सवाल उठाये हैं. रमना ने कहा है कि इससे जांच एजेंसी की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है. सीजेआई ने कहा, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पुलिस की छवि तार-तार हो गई है. अक्सर पुलिस अधिकारी हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है...राजनीतिक प्रतिनिधि तो बदलते रहते हैं, लेकिन आप हमेशा रहोगे. ठडेमोक्रेसीः जांच एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारीठ विषय पर एक व्याख्यान को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन से अब तक भारत में पुलिस सिस्टम में बदलाव हुआ है, लेकिन समय बीतने के साथ, सीबीआई गंभीर सार्वजनिक निगरानी के दायरे में आ गए हैं.

सीजेआई एन वी रमना ने कहा, जांच एजेंसी को स्वतंत्र, स्वायत्त बनाना समय की मांग है. एक ही अपराध की कई एजेंसियों से जांच उत्पीड़न की ओर ले जाती है. एक बार अपराध दर्ज होने के बाद यह तय किया जाना चाहिए कि कौन सी एजेंसी इसकी जांच करेगी. इन दिनों एक ही मामले की कई एजेंसियों द्वारा जांच की जाती है. यह संस्था को उत्पीड़न के एक उपकरण के रूप में दोषी ठहराए जाने से बचाएगा. एक बार रिपोर्ट किए जाने के बाद संगठन को यह तय करना चाहिए कि कौन सी एजेंसी जांच का जिम्मा संभालेगी. सीजेआई ने कहा, जब आप झुकेंगे नहीं तो आपको वीरता के लिए जाना जाएगा.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, पुलिसिंग केवल नौकरी नहीं बल्कि एक कॉलिंग है. भारत में अंग्रेजों ने कानून पेश किया जहां शाही पुलिस बनाई गई थी जिसे भारतीय नागरिकता को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया था. राजनीतिक आकाओं द्वारा पुलिस का दुरुपयोग कोई नई विशेषता नहीं है. पुलिस को आम तौर पर कानून का शासन बनाए रखने का काम सौंपा जाता है और यह न्याय वितरण प्रणाली का अभिन्न अंग है. औचित्य की मांग पुलिस को पूर्ण स्वायत्तता देना है. सभी संस्थानों को लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना और मजबूत करना चाहिए. किसी भी सत्तावादी प्रवृत्ति को पनपने नहीं देना चाहिए.

सीजेआई ने कहा, भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पुलिस की छवि को गहरा धक्का लगा है. अक्सर पुलिस अधिकारी हमारे पास आते हैं और शिकायत करते हैं कि सरकारों में बदलाव के साथ उन्हें परेशान किया जा रहा है. लेकिन आपको याद रखना होगा कि जनप्रतिनिधि समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन आप स्थायी हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी संस्थान उनके नेतृत्व की तरह अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन कुछ अधिकारी बड़ा बदलाव ला सकते हैं.

राज्यसभा में बीजेपी ने लगाया शतक

1988 के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली पार्टी बनी

नई दिल्ली (ईएमएस)। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद सदन में बिल पर बिल पेश कर रही हैं। लोकसभा में बहुमत होने की वजह से बिल पास हो जा रहा था। दिक्कत होती थी राज्यसभा में और गुणा-गणित करना पड़ता था। क्षेत्रिए पार्टियों को मनाना पड़ता था। फिर वोटिंग होती थी। लेकिन अब बीजेपी के दिन आसान होने वाले हैं। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में किसी बिल को पास कराने के लिए पार्टी को कुछ कम मेहनत करनी होगी क्योंकि अब राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 100 के आंकड़े को छू गई है। बीजेपी 1988 के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली पार्टी बन गई है। राज्यसभा में अब बीजेपी के पास कुल सांसदों की संख्या 101 हो गई है।

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्यसभा की 13 सीटों पर चुनाव हुए। ये 13 सीटें छह राज्यों की हैं। जिसमें पंजाब से 4 सीट, केरल से 3 सीट, असम से दो और हिमाचल प्रदेश, नागालैंड व त्रिपुरा से एक-एक सीट शामिल हैं। बीजेपी ने इस 13 में से चार सीटें अपने नाम कर ली है। बीजेपी ने पूर्वोत्तर के तीन राज्य असम, नागालैंड और त्रिपुरा से राज्यसभा की चार सीटें अपने नाम की है। जिससे इस क्षेत्र से बीजेपी के राज्यसभा सदस्यों की संख्या भी बढ़ गई है। असम की दोनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष माणिक साहा गुरुवार को पूर्वोत्तर राज्य की एकमात्र सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। एस फांगनोन कोन्याक गुरुवार को नगालैंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्विरोध चुनी गईं।

रुस भारत को दे रहा सस्ता तेल, साथ ही गेंहू की कीमत भी बढ़ी

नई दिल्ली (ईएमएस)। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में भारत को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। भारत में गेहूं की कीमतें एमएसपी से ज्यादा हो चुकी हैं। मिस्त्र जैसे देश ने गेहूं के आयात के लिए भारत से संपर्क किया है। गेहूं का एमएसपी 2,050 रुपये ही है, जबकि बाजार में दाम बढ़कर 2,250 से लेकर 2,300 रुपये तक हो चुका है। इसके अलावा भारत को रूस से सस्ता कच्चे तेल भी मिलने जा रहा है। रूस ने भारत को इस साल 15 मिलियन बैरल कच्चा तेल देने का फैसला लिया है। साथ ही तेल पर 35 डॉलर प्रति बैरल तक का डिस्काउंट भी दिए जाने की तैयारी है। मामले से जुड़े लोगों का कहना हैं कि रूस ज्यादा से ज्यादा तेल भारत को बेचने चाहता है, क्योंकि पश्चिमी देशों की ओर से लगी पाबंदियों के चलते वह मुश्किल के दौर में है।

एशिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश भारत उन देशों में से एक है, जिसने अंतरराष्ट्रीय दबावों और पाबंदियों के बीच भी रूस से तेल की खरीद को बढ़ाने का फैसला लिया है। दरअसल अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस से तेल के आयात में कमी करने का फैसला लिया है। इसके बाद में रूस एशिया में ही तेल के खरीददारों की तलाश करने में जुटा है। खासतौर पर चीन और भारत से रूस को बड़ी उम्मीद है। दोनों ही देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत कई मंचों पर रूस का विरोध नहीं कर उसके खिलाफ लाए गए प्रस्तावों से ही दूरी बना ली।

रूस ने भारत को तेल की खरीद में रुपये-रूबल पेमेंट सिस्टम को भी अपनाने की सुविधा देने की बात कही है। यह स्थिति भारत के लिए और अच्छी होगी और उसे अपने विदेशी मुद्रा भंडार से खर्च नहीं करना होगा। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर मुहर नहीं लगी है। रूस के विदेश मंत्री सेरजे लावरोव गुरुवार को दो दिन के भारत दौरे पर आए हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान मसले पर बातचीत होगी है। रूस से तेल की खरीद की प्रक्रिया भारतीय कंपनी इंडियन ऑइल के जरिए होगी। अभी जानकारी नहीं है, कि अधिकतम कितने तेल की खरीद भारत करेगा, लेकिन कम से कम 15 मिलियन बैरल का आयात करने पर सहमति बन सकती है।

पीएम मोदी कर्नाटक आकर भष्ट्रचार से लड़ने की बात करे, तब पूरा कर्नाटक हंसेगा : राहुल गांधी

बेंगलुरु (ईएमएस)। कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अगर आज भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करें,तब लोग उन पर हंसने वाले हैं। राहुल ने कहा, पहले मोदी चुनाव के समय भ्रष्टाचार की बात करते थे। आज अगर मोदी कर्नाटक में आकर भ्रष्टाचार की बात करें और कहें कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं,तब शायद पूरा कर्नाटक हंसाना शुरू कर देगा और वह यह बात हिंदुस्तान में कहीं नहीं कह सकते हैं।ठदो दिवसीय कर्नाटक दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का जो लक्ष्य है, वह गरीबों का पैसा छीनकर 3-4 सबसे बड़े उद्योगपतियों के हवाले करने का है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास मूल रूप से फाइनेंशियल ट्रांसफर मैकेनिज्म है। इसका मतलब है कि गरीबों से पैसा लो और 2-4 उद्योगपतियों को दे दो। यहीं भाजपा का सिस्टम है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के सामने महंगाई और बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल ने कहा, नोटबंदी, गलत जीएसटी और कृषि कानून के कारण देश को नुकसान हुआ। आज देश की हालत यह है कि भाजपा चाहकर भी देश में रोजगार नहीं दे सकती, क्योंकि छोटे और लघु उद्योगों को भाजपा ने खत्म कर दिया है।ठ बेंगलुरु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ठकर्नाटक में हमेशा कांग्रेस पार्टी की भावना रही है। यह कांग्रेस की स्वाभाविक स्थिति है। हमारे मन में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हमें 150 से कम सीटें नहीं मिलेंगी। हम कर्नाटक को विकास के रास्ते पर वापस लाएंगे। यह पता लगाना बहुत आसान है कि कर्नाटक में असली काम कौन कर रहा है। हमें उस काम के आधार पर टिकट तय करना चाहिए जो वह व्यक्ति कांग्रेस के लिए कर रहा है। हमें कड़ी टक्कर के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हमें सरकार बनाने के लिए लड़ना है।ठ

सरिस्का टाइगर रिजर्व में 5वें दिन काबू में आई आग, हेलिकाप्टर से किया जा रहा रेस्क्यू

अलवर (ईएमएस)। अलवर स्थित प्रसिद्ध सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगल में धधक रही आग पांचवें दिन काबू में आ गई है। उसके बाद वायु सेना के हेलिकॉप्टर से चलाया रहा रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। हालांकि आज भी हेलिकॉप्टर ने आग बुझाने के लिए सुबह सीलीसेढ़ झील से पानी लाकर जंगल में बौछार मारनी शुरू की थी।

बाद में आग पर मोटे तौर पर काबू पा लेने के कारण तीन चक्कर के बाद हेलिकॉप्टर रोक दिया गया। अब जमीनी स्तर पर वनकर्मी और ग्रामीण ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। आग पर काबू हो जाने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है।

इस मामले में सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया सरिस्का जंगल में लगी आग को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बात हुई। मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि आग पर शाम तक या कल सुबह तक काबू पा लिया जाएगा। प्रशासन ने सरिस्का की आग पर मोटे तौर पर नियंत्रण कर लिया है एवं अब एक सीमित जगह पर थोड़ी आग बाकी है, जिसे भी जल्द बुझा दिया जाएगा। यह पहाड़ी इलाका है जहां फायर ब्रिगेड पहुंचने में परेशानी आई थी पर हेलिकॉप्टर के इस्तेमाल से आग पर काबू पा लिया गया है।

400 से ज्यादा वनकर्मी व ग्रामीण लगातार इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व की अकबरपुर रेंज में बीते 27 मार्च को दोपहर में आग लगी थी। उसके बाद पहले इस पर काबू पा लिया गया था, लेकिन रात को चली हवाओं के कारण यह फिर भड़क गई थी। दोबारा भड़की आग फिर जल्दी से काबू में नहीं आई और इसका फैलाव 8 से 10 किलोमीटर एरिया में हो गया था। इस दौरान भी वन विभाग ने अपने स्तर पर ही आग पर काबू पाने के प्रयास किए थे। लेकिन बात नहीं बनी और आग फैलती गई।

उसके बाद आग पर काबू पाने के लिए सेना की मदद मांगी गई थी। दो दिन पहले मंगलवार को वायु सेना के दो हेलिकॉप्टर यहां भेजे गये। उन्होंने सिलीसेढ़ झील से पानी लाकर जंगल में गिराना शुरू किया। इसके बावजूद आग का फैलाव होता गया।

पांच महीने में 724 रुपये बढ़े कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम

नई दिल्ली (ईएमएस)। सरकारी तेल कंपनियां जिस समय पेट्रोल-डीजल कीमतों में कोई बदलाव नहीं कर रहीं थी, उस समय उनका पूरा जोर एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाने पर था। इसी कड़ी में शुक्रवार को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपये का बड़ा इजाफा किया गया, लेकिन आपको पता है कि पिछले पांच माह में इसकी कीमतें 724 रुपये बढ़ चुकी हैं, हम बात कर रहे हैं कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की। सरकारी तेल कंपनियों ने 4 नवंबर, 2021 से 21 मार्च, 2022 तक करीब साढ़े चार महीने तक पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया। हालांकि, इस दौरान कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 724 रुपये का जोरदार इजाफा कर दिया है। कंपनियां 22 मार्च के बाद से पेट्रोल-डीजल के रेट में भी लगातार इजाफा कर रही हैं और देश के अधिकतर शहरों में पेट्रोल वापस 100 रुपये पार चला गया है।

सरकारी तेल कंपनियों ने 1 नवंबर, 2021 को 19.2 किलोग्राम वाले कामर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 260 रुपये का इजाफा किया था। इसके बाद 1 दिसंबर को फिर 103.50 रुपये दाम बढ़ा दिए। तेल कंपनियों ने 2022 के शुरुआती दो महीनों में कोई इजाफा नहीं किया। यानी जनवरी और फरवरी में कामर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मामूली कटौती कर दी। इसके बाद 1 मार्च, 2022 को वापस कीमतों में 105 रुपये का इजाफा किया गया। कंपनियों ने 22 मार्च को फिर 9 रुपये दाम घटा दिए लेकिन 1 अप्रैल, 2022 को फिर से 250 रुपये का इजाफा किया। इस तरह कंपनियों ने महज पांच महीने के भीतर ही कामर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 724.50 रुपये का इजाफा कर दिया है।

सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बड़ा इजाफा कर दिया है। 22 मार्च को दिल्ली सहित तमाम शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए। इसके बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर का मूल्य 949.50 रुपये पहुंच गया था. कंपनियों ने एक बार दाम बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया,तब इसका असर सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी सहित पेट्रोल-डीजल पर भी बखूबी दिखाई दिया है।

पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के 3 सहयोगी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद

श्रीनगर (ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षाकर्मियों को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि सुरक्षाकर्मियों ने 3 आतंकवादियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया है।इनका संबंध आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से है। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। खबरों के अनुसार पुलवामा पुलिस ने 55 आरआर और 182/183 बीएन सीआरपीएफ के साथ आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया। वे ज़िले में आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करा रहे थे। इनके पास से एक एके राइफल, तीन मैगज़ीन और 69 एके राउंड बरामद हुए।

इसके पहले शोपियां जिले में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाबलों ने दक्षिण कश्मीर में शोपियां जिले के तुर्कवांगम इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी बीच आतंकवादी ने गोलीबारी शुरू कर दी और सर्च ऑपरेशन मुठभेड़ में तब्दील हो गया।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिये मोदी सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के साथ ही पूर्वोत्तर के 3 राज्यों नागालैंड, असम और मणिपुर के अनेक जिलों से आर्म्ड फोर्सज स्पेशल पावर्स एक्ट (एएफएसपीए) को हटा दिया गया है। इसके पहले यह विशेष आदेश पूरे राज्य पर लागू था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी के मुताबिक इस बाबत इन तीनों राज्यों की सुरक्षा समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय के आला अधिकारी के मुताबिक विशेषकर पिछले 3 वर्षों में जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रालय की कमान संभाली तब से उन्होंने लगातार पूर्वोत्तर में संवाद बढ़ाया और उग्रवाद समाप्त करने के लिए अनेक समझौते किए जाने पर विशेष जोर दिया। इसी प्रयासों के चलते इन राज्यों में आर्म्ड फोर्सज स्पेशल पावर्स एक्ट की भी समीक्षा की गई और इस समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इस विशेष पावर को अनेक इलाकों से हटाया जा सकता है। लिहाजा 1 अप्रैल 2022 से इसका दायरा कम करने का निर्णय लिया गया। नए आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल से असम के 23 जिलों से इसे पूरी तरह से और 1 जिले से इसे आंशिक रूप से हटाया जा रहा है। इसके साथ ही मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस थानों से इस कानून को हटाया गया है। नागालैंड के 7 जिलों के 15 पुलिस थानों से इसे हटाया गया है। गृह मंत्रालय के आला अधिकारी के मुताबिक पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों से भी इस विशेष अधिनियम को धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। मसलन अरुणाचल प्रदेश में इसे धीरे-धीरे कम किया गया है। मौजूदा समय में वहां सिर्फ तीन जिलों और एक अन्य जिले के दो पुलिस थाना क्षेत्रों में यह विशेष अधिनियम लागू है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बाबत कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अटूट प्रतिबद्धता के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र जो दशकों से उपेक्षित था अब शांति समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है।यह भी ध्यान रहे कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग 7000 से ज्यादा हथियार धारकों ने पूर्वोत्तर में आत्मसमर्पण किया है। जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बोडो समझौता कराया था। इसके बाद करबी आंगलांग समझौता किया गया। त्रिपुरा में उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए 2019 में एनएलएफटी समझौता हुआ और उसके बाद इसी सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम मेघालय सीमा विवाद को निपटाने की दिशा में समझौता किया गया। इसके तहत 12 विवादित बिंदुओं में से 6 बिंदुओं पर दोनों राज्य सहमत हो गए हैं और बाकी के 6 विवादित बिंदुओं पर बातचीत लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक जल्द ही इन बिंदुओं को भी सुलझा लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को लगा झटका, एसआईटी वाली मांग खारिज

नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई से जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि क्षमा करें, इस खारिज किया जाता है।ठशीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने देशमुख के खिलाफ एक एसआईटी द्वारा अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता सी.ए.सुंदरम ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार ने देशमुख के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच पर आपत्ति जाहिर की हैं, जिसमें सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई निदेशक थे। सुंदरम ने जोरदार तर्क दिया कि जायसवाल प्रासंगिक समय पर महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी और पुलिस स्थापना बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, जिसने संबंधित पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की जांच की।

पीठ में न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश भी शामिल थे। उन्होंने कहा, हम इस मामले को नहीं छूएंगे।ठ सुंदरम ने कहा कि वर्तमान सीबीआई प्रमुख या तो संभवतः एक आरोपी होंगे या निश्चित रूप से गवाह होंगे। उन्होंने कहा, ठमैं पक्षपात की संभावना में नहीं जा रहा हूं, एक व्यक्ति जो गवाह या आरोपी के रूप में प्रासंगिक है, वह सीधे तौर पर शामिल था।ठ सुंदरम ने जोर देकर कहा कि ठयदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है तो आपका प्रभुत्व एसआईटी या मामले की जांच करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है।ठदलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि वह राज्य सरकार की याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। सीबीआई ने पिछले साल अप्रैल में देशमुख और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत मामला दर्ज किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता देशमुख गृह मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पुलिस तबादलों और पोस्टिंग के लिए रिश्वत लेने के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

कार्टून कोना

कोयले की आपूर्ति प्रभावित होने से मंडराने लगा बिजली संकट, उत्तर भारत के कई राज्यों में हो रही है कटौती

नई दिल्ली। घरेलू स्तर के साथ आयातित कोयले की सप्लाई प्रभावित होने से बिजली संकट का खतरा मंडराने लगा है। कई राज्यो में बिजली की घंटों कटौती शुरू हो चुकी है जिससे औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। महाराष्ट्र अपने पावर प्लांट के लिए कोयले की कमी बता रहा है। गुजरात भी बिजली संकट से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बिजली की घंटों कटौती हो रही है। बिजली की मांग में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए पावर एक्सचेंज आईईएक्स में एक अप्रैल को बिजली की कीमत प्रति यूनिट 20 रुपए के स्तर तक पहुंच गई। जानकारों का कहना है इस साल समय से पहले उत्तर भारत में गर्मी अधिक पड़ने से भी बिजली की मांग में बढ़ोतरी हुई है। इस साल मार्च में बिजली की खपत पिछले साल मार्च के मुकाबले 4.6 फीसद अधिक रही।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 3.95 लाख मेगावाट है और इनमें से 2.35 लाख मेगावाट थर्मल बिजली है। 2.10 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन कोयले से होता है तो लगभग 25,000 मेगावाट की क्षमता गैस आधारित है। भारत अब भी मुख्य रूप से बिजली के लिए कोयला आधारित पावर प्लांट पर ही निर्भर करता है। फिलहाल मांग में बढ़ोतरी के बावजूद पावर प्लांट का पीएलएफ (प्लांट लोड फैक्टर) 60 फीसद से कम है। 2.10 लाख मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट में से लगभग 40,000 मेगावाट के पावर प्लांट आयातित कोयले पर निर्भर करते हैं क्योंकि उनके प्लांट की संरचना ऐसी है कि वे घरेलू कोयले से नहीं संचालित हो सकते हैं। बाकी के पावर पलांट भी कोयले की कमी को दूर करने के लिए 10 फीसद तक आयातित कोयले का इस्तेमाल करते है।

रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोयले के दाम में भारी बढोतरी हुई है। यूरोप में कोयले की मांग काफी बढ़ गई है क्योंकि वहां प्राकृतिक गैस की किल्लत हो गई है। इससे आयातित कोयले की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इकरा की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कीमत बढ़ने से आयातित कोयले से चलने वाले पावर प्लांट की उत्पादन लागत में पिछले एक साल में तीन रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हो चुकी है। घरेलू स्तर पर भी दो दिन पहले तक पावर प्लांट के पास औसतन नौ दिन का कोयला स्टॉक था जबकि यह स्टॉक 24 दिन का होना चाहिए।

आयातित पावर प्लांट के पास कोयले का स्टाक नाजुक स्थिति में है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के निदेशक एवं ऊर्जा विशेषज्ञ सलिल गर्ग ने बताया कि घरेलू स्तर पर कोयले की कमी का अलर्ट जारी होने के साथ गर्मी में अचानक तेजी से बिजली की मांग अधिक हो गई। यही वजह है कि एनर्जी एक्सचेंज में बिजली की कीमत 20 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच गई, लेकिन सभी राज्य इतने सक्षम नहीं है कि 20 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद कर उपभोक्ताओं को दे सके। इसलिए बिजली की कटौती हो रही है। गर्ग ने बताया कि बहुत लंबे समय तक ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, कोयले की सप्लाई तेज होते ही स्थिति सामान्य होने लगेगी

जन हितैषी

अफस्पा का औचित्य

केंद्र सरकार ने गुरुवार को उत्तर पूर्वी राज्यों की दृष्टि से बड़ा कदम उठाते हुए असम, नगालैंड व मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) का क्षेत्र सीमित करने का फैसला किया। यह विशेष कानून अब इन राज्यों के कुछ खास इलाकों तक सीमित रहेगा। इसका एरिया घटा दिया गया है। उत्तर-पूर्व के राज्यों से इस कानून को हटाने के लिए लंबे समय से मांग हो रही है। हालांकि केंद्र ने अभी इसे पूरी तरह हटाने की बजाए कुछ गड़बड़ी वाले क्षेत्रों तक सीमित करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। शाह ने कहा कि दशकों से उपेक्षित महसूस कर रहे उत्तर-पूर्वी राज्यों के प्रति पीएम नरेंद्र मोदी की वचनबद्धता के कारण वहां शांति, समृद्धि व विकास का नया युग नजर आ रहा है। इस मौके पर मैं उत्तर-पूर्व की जनता को बधाई देता हूं। गृह मंत्री ने कहा कि अफस्पा के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में कमी इन राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में सुधार, तेजी से विकास व तमाम शांति समझौतों के कारण हो सकी है। उत्तर पूर्व में मोदी सरकार ने शांति बहाल की है। अफस्पा का दायरा सीमित किया जाना एक सकारात्मक कदम है। सेना को विशेषाधिकारों से लैस करने वाले इस बेहद कड़े कानून को पूर्वोत्तर की जनता ने लंबे समय तक एक खतरनाक और दमनकारी कानून के रूप में देखा और झेला है। इस कानून की आड़ में कई बेगुनाह नौजवान सैन्य कार्रवाई का शिकार बने। इसलिए अफस्पा को हटाने की लंबे समय से मांग होती रही है। मणिपुर की सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला तो इस कानून के विरोध में 16 साल तक अनशन पर रहीं।

अफस्पा छह दशक पुराना कानून है। इसे एक सितंबर 1958 को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड में लागू किया गया था। इन राज्यों की सीमाएं चीन, म्यांमा, भूटान और बांग्लादेश से मिलती हैं। इन राज्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की दृष्टि से काफी संवेदनशील बताते हुए इस कानून को लागू किया गया था। वर्ष 1986 में हुए मिजो समझौते के तहत मिजोरम में अफस्पा स्वतः ही खत्म हो गया था। इसके बाद 2015 में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद त्रिपुरा से भी अफस्पा हटा लिया गया। दरअसल, पूर्वोत्तर का उग्रवाद सरकारों के लिए बड़ी चुनौती रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में अलग प्रदेश की मांग को लेकर अलगाववादी संगठन हिंसा का सहारा लेते रहे हैं। इन संगठनों को देश के बाहर से मदद मिलती है, यह तथ्य भी किसी से छिपा नहीं है। अफस्पा का मूल मकसद उग्रवादी हिंसा को कुचलना था। लेकिन इस कानून की आड़ में नागरिकों पर जो जुल्म हुए, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले थे।

जम्मू-कश्मीर में भी अफस्पा 1990 से लागू है। हालांकि हालात को देखते हुए केंद्र ने वहां से इसे हटाने से इनकार कर दिया है। अफस्पा के तहत सेना को असीमित अधिकार हासिल हैं। इस कानून के तहत सेना किसी को भी बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकती है, बिना वारंट किसी भी घर की तलाशी ले सकती है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि अफस्पा का इस्तेमाल एक दमनकारी कानून के रूप में ज्यादा हुआ है। इस कानून के तहत सशस्त्र बलों को बेलगाम शक्तियां दे दी गईं। इसीलिए बेजा इस्तेमाल तो बढ़ना ही था। इस विशेष कानून को बनाने के पीछे मूल भावना तो यह थी कि अशांत क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए इसका सहारा लिया जाएगा। इसीलिए सशस्त्र बलों को खुल कर सारे अधिकार दिए गए। अफस्पा के तहत सशस्त्र बलों को बिना अनुमति किसी भी घर की तलाशी लेने, किसी को गिरफ्तार कर लेने और यहां तक कि कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चला देने जैसे अधिकार हासिल हैं। अगर सशस्त्र बलों की कार्रवाई के विरोध में लोग हिंसा करते हैं और उस सूरत में सशस्त्र बलों की गोली से लोग मारे जाते हैं तब भी गोली चलाने वाले बलों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की इजाजत यह कानून नहीं देता। इसीलिए अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जब निर्दोष नागरिक सशस्त्र बलों की ज्यादती का शिकार होते रहे हैं। याद किया जाना चाहिए कि मणिपुर में वर्ष 2000 में असम राइफल्स के जवानों ने दस निर्दोष लोगों को मार डाला था। देश की आतंरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की है। इसे सुनिश्चित करने के लिए ही अफस्पा जैसा कठोर कानून जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू किया गया। पूर्वोत्तर के राज्य भी उग्रवाद के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। पड़ोसी देशों से उग्रवादी संगठनों को मदद, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी यहां के लिए बड़ा संकट है। लेकिन इस आंतरिक सुरक्षा की आड़ में सशस्त्र बल स्थानीय नागरिकों का जिस तरह से दमन करते रहे हैं, उससे इन राज्यों के लोगों में इन बलों के प्रति नफरत और आक्रोश भर गया है।

माननीयों का वेतन-भत्ताः पंजाब के मान सरकार की अनुकरणीय पहल

बीसवीं सदी की दो बड़ी खोज हैं - महात्मा गाँधी और एटम बम, जिनमें से सदी के आखिर में कोई एक ही जीतेगा। डॉ. राममनोहर लोहिया का यह कथन संसाधनों के असमान वितरण और रूस-यक्रेन युद्ध के संदर्भ में महसूस किया जा सकता है, जिसमें सम्राज्यवादी कुप्रवृत्ति का मोहरा बने आम नागरिक दम तोड़ते नजर आते हैं। 'तीन आना बनाम पन्द्रह आने' के उनके दावे को तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष महालनोबिस ने पुष्ट किया कि किस तरह आम आदमी रोजाना 3 आने (चवन्नी का चैथाई भाग) पर पारिवारिक भरण पोषण के लिए विवश है जबकि प्रधानमंत्री पर प्रतिदिन 25 हजार रुपये खर्च होते हैं। दुःखद है कि महामारी की दीर्घपीड़ा से कराहते जन से अनुदारपूर्ण वसूली सत्ता संवरण में व्यय किया जाता रहा है।

दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां जनप्रतिनिधि अपने वेतन, भत्ते, पेंशन व सुविधाओं का स्वयं निर्णय लेते हैं। यह सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भारत में भी संभव है। इस संबंध में आयोग गठन की सलाह न केवल उपेक्षित रही बल्कि वर्ष 1954 से अब तक पेंशन अधिनियम में मनमाना संशोधन कर देशसेवा के इस मिशन को अप्रत्याशित लाभ में परिवर्तित कर लिया गया।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते मध्यप्रदेश में 1.70 लाख रुपये प्रतिमाह लेने वाले मंत्रियों का आयकर राज्य सरकार ने वहन करने का निर्णय लिया है। इससे 43 करोड़ रुपये मंत्रियों के इनकम टैक्स के भुगतान पर खर्च होगा। महामारी काल की पूर्णबंदी से रुके पहियों के बावजूद विधायकों के भत्तो पर साढ़े चार गुना से अधिक भुगतान किया गया। प्राप्त आंकड़ो के अनुसार गत 5 वर्षों में राज्य के विधायको के वेतन पर 35.03 करोड़ रुपये खर्च हुए जबकि विविध भत्तों पर 121 करोड़ रुपये व्यय किये गये जिसमें अकेल यात्रा भत्ता पर 38.03 करोड़ रुपये खर्च हुए। चुनाव जीतकर एक दिन के लिए सदन पहुंचने वाले नेता भले ही फिर कभी चुनाव न लड़ें लेकिन वे आजीवन पेंशन और सुविधायें प्राप्त करने के हकदार हैं। यदि वह कई बार चुनाव जीत चुका है तो तदानुसार उसकी पेंशन प्रति कार्यकाल के हिसाब से बढ़ती है, इस तरह वह पांच लाख रुपये प्रतिमाह से अधिक पेंशन पाने का अधिकारी हो जाता है। इसके अलावा चुनाव जीतते ही माननीयों की संपत्ति अचानक कई गुना बढ़ी दर्ज होती है फिर भी उन्हें विभिन्न मद में सुविधायें व भत्ते मिलते रहते हैं। पड़ौसी राज्य उत्तरप्रदेश में तो पूर्व विधायकों को प्रतिमाह 30 हजार रुपये पेशन के अलावा प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए दो हजार रुपये अलग से मिलते हैं। साथ ही सालाना एक लाख रुपये का रेल कूपन भी मिलता है। ऐसे में केवल सरकारी कर्मचारियों का पेन्शन बंद करना कहाँ का सामाजिक न्याय है? जबकि अवकाश प्राप्त कर्मचारी का परिवार पेंशन पर ही निर्भर है।

गांधीवादी और संघ विचारधारा वाली सरकारों की उपेक्षा का तिलिस्म तोड़ती पंजाब की नवनिर्वाचित 'आप' की मौजूदा व्यवस्था पर रोक से लोकतंत्र में विश्वास की जो अलख जगाई है उससे वित्तीय संकट से जूझ रहे देश को नई दिशा मिलेगी । इस निर्णय से पंजाब राज्य के विधायकों को केवल एक कार्यकाल अर्थात् 75 हजार 150 रुपये के बराबर पेंशन मिलेगी। अपेक्षा की जाती है कि अन्य सरकारें भी ऐसे मूल्यों का अनुकरण करेंगी। (लेखक- राकेश कुमार वर्मा / ईएमएस)

शब्द पहेली - 7243

बाएँ से दाएँ

1. आदत, स्वभाव-4
4. सुरक्षित-4
7. जरुरतमंद-5
9. भीगा हुआ-2
11. मक्का-मदीना की यात्रा-2
12. सोना, धतुरा-3
14. धक्का देना-4
15. खानाबदोश, बंजारा-4
16. अंधेरा, अंधकार-3
18. खामी, बुरी आदत-2
19. ईसाई साध्वी-2
21. नायक का विलोम-5
25. करिश्मा, करामात-4
26. महीन व मंहगे कपड़े का एक प्रकार -4

ऊपर से नीचे

1. अंग्रेज, विदेशी-3
2. लीन, मगन-2
3. पैंदा, तला-2
4. रिश्तेदार-2
5. थूक, लेस-2
6. तहजीब, सलीका-3
8. देह, काया-3
10. टोने-टोटकों वाली किताब-5
11. स्वदेशवासी -5
12. कपड़े की दीवार-3
13. अनुमान, आकलन-3
17. राजी करना-3
18. चश्मा-3
20. अनुकृति-3
21. पत्र, चिट्ठी-2
22. होठ, अधर-2
23. मृत्यु देवता, यमराज-2
24. बीता हुआ दिन-2

शब्द पहेली -7242 का हल

■	त	ल	ब	■	ट	म	ट	म
प	■	■	द	स्त	क	■	■	हा
र	■	ना	नी	■	ला	श	■	ज
ख	ल	ना	य	क	■	ब	त	न
■	ल	■	त	■	ना	■	री	■
म	ना	ही	■	ह	क	ब	का	ना
हा	■	ना	क	■	क	ल	■	वि
व	■	■	स	पा	ट	■	■	का
त	व	वा	र	■	ना	ह	क	■

Jagrutidaur.com, Bangalore

सच छुपाने के यह 'इश्तेहारी झूठ'

राष्ट्रीय स्तर पर चलाये जा रहे स्वच्छता मिशन पर केंद्र सरकार अब तक अरबों रूपये ख़र्च कर चुकी है। इस अभियान पर प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट में सैकड़ों करोड़ की धनराशि ख़र्च करने की घोषणा की जाती है। ग़रीबों के मकानों में व शौचालय विहीन मकानों में शौचालय बनाने के लिये सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पैसे भी दिये गये हैं। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिये राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार का यथासंभव सहयोग कर रही हैं। यह योजना कितनी सफल हुई और कितनी असफल कितनी पूर्ण हुई और कितनी अपूर्ण, ज़मीनी स्तर पर यह जाने बिना ही विभिन्न राज्य सरकारों ने अपनी पीठ थपथपानी भी शुरू कर दी है। अपनी झूठी सफलता के परचम बड़ी ही बेशर्मी से लहराये जाने लगे हैं। अफ़सोस तो यह है कि इस झूठ के प्रचार में भी सरकार जनता के टैक्स का ही करोड़ों रुपया पानी में बहा रही है।

पिछले दिनों अपने बिहार प्रवास के दौरान कई ग्राम पंचायतों में ऐसे ही झूठे दावों के प्रचार दृश्य देखने को मिले। बिहार राज्य का दरभंगा ज़िला किसी समय में न केवल राज्य के सबसे समृद्ध ज़िले के रूप में जाना जाता था बल्कि इसे मिथिलांचल का सिरमौर भी कहा जाता था। इसी दरभंगा ज़िले में बहेड़ी मुख्य मार्ग पर स्थित है ग्राम पंचायत चंदनपट्टी। इस ग्राम पंचायत से होकर गुज़रने वाले मुख्य मार्ग की काली चमचमाती सड़कें और इनपर तेज़ रफ़्तार दौड़ते वाहनों को देखकर प्रथम दृष्टया तो यही लगेगा कि आधारभूत सुविधाओं से युक्त इस क्षेत्र में वास्तव में विकास के पंख लग गये हैं। इन्हीं मुख्य मार्गों पर सरकार के झूठे दावों को दर्शाने वाले अनेक विशाल बोर्ड भी लगे हुये हैं जिनमें सरकार द्वारा अपना गुणगान किया गया है। इसी चंदन पट्टी पंचायत के मुख्य मार्ग पर लगे एक विशाल होर्डिंग ने मुझे आकर्षित किया। ज़िला जल एवं स्वच्छता समिति (ग्रामीण विकास अभिकरण),दरभंगा की ओर से जारी इस होर्डिंग में यह दावा किया गया है कि यह ग्राम पंचायत 'खुले में शौच मुक्त' हो चुकी है। इसमें गांव को स्वच्छ रखने की प्रतिबद्धता का दावा करते हुये ग्राम पंचायत चंदन पट्टी द्वारा आपका स्वागत भी किया गया है। अपने दावों को और मज़बूत करने के लिये होर्डिंग में ग्राम पंचायत के खुले में शौच मुक्त की 27 -09 -2019 की तिथि भी अंकित की गयी है।

परन्तु जब आप इसी ग्राम पंचायत के भीतरी या बाहरी मार्गों पर प्रातःकाल अथवा सूर्यास्त के बाद भ्रमण करें फिर आप को इस झूठे प्रचार करने वाले होर्डिंग व दावों की हक़ीक़त नज़र आ जायेगी। इसमें कोई शक नहीं कि सड़क किनारे बैठ कर व खुले खेतों व पगडंडियों पर शौच करने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी कमी ज़रूर आयी है। किसी समय में तो शौच की दुर्गन्ध के चलते सड़क से गुज़रना भी मुहाल था। परन्तु ग्राम पंचायत पूरी तरह से अमुक तिथि को खुले में शौच मुक्त हो चुकी है यह दावा भी पूरी तरह ग़लत व झूठा है। आज भी जगह जगह लोग खुले में शौच त्यागते तथा उसकी दुर्गन्ध व उसपर भिनाभिनाती मक्खियां,सब कुछ आसानी से देखने को मिलेगा। रहा सवाल प्रचार बोर्ड में ग्राम पंचायत को स्वच्छ रखने की प्रतिबद्धता का दावा करने का तो यह दवा तो ऐसा है जिसे महाझूठ भी कहा जा सकता है और ऐसे झूठ को गिन्नीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकार्ड में भी आसानी से दर्ज किया जा सकता है।

गांव के भीतर घनी आबादी से गुज़रने वाली सड़क से यदि आप गुज़रें तो कई जगह सड़कों पर कीचड़,शौच,नाली की ओवर फ़्लो गंदिगी देखकर ही आप यक़ीनन आधे रास्ते से ही वापस आ जायेंगे। गांव की बड़ी आबादी इसी कीचड़ व दुर्गन्धयुक्त वातावरण में रहती है और दिन में कई कई बार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये इन्हीं रास्तों से गुज़रने के लिये मजबूर है। पूरे गांव में नाले नालियां व भूतलीय नाले पूरी तरह से जाम पड़े हैं। इस गंदिगी और इसमें संतुष्ट होकर रहने वालों को देखकर आपको यह पता चल जायेगा कि बिहार में जापानी बुख़ार,काला ज़ार और इंसेफ़िलाइटिस जैसी बीमारियों के फ़ैलने की वजह क्या है। होर्डिंग के झूठे दावों और ज़मीनी हक़ीक़त के अंतर को देखिये फिर आसानी से पता चलेगा कि किस तरह सरकार झूठ का प्रचार कर और सच से आँखें मूंद कर महामारियों को स्वयं नेवता दे रही है।

स्थानीय लोगों से जानकारी हासिल करने पर पता चला कि सरकार द्वारा शौचालय विहीन लोगों को शौचालय बनाने हेतु 12 हज़ार रुपये प्रति आवास की दर से पैसे दिये गये हैं। इनमें दो हज़ार रुपये तो धन वितरण करने वाले कथित तौर पर हड़प जाते हैं जबकि केवल दस हज़ार रूपये बांटे जाते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पैसे भी उसे दिये जाते हैं जो पहले अपने ख़र्च से शौचालय बनाकर और उस निर्मित शौचालय का फ़ोटो खींचकर सरकार को जमा करता है। बताया जाता है कि इस में कई ऐसे लोगों को भी पैसे मिले जिनके मकानों में शौचालय पहले से ही मौजूद थे। जबकि अनेक शौचालय विहीन मकान वालों को पैसे इसलिये नहीं मिल सके क्योंकि वे अपनी कमाई से शौचालय बनाकर उसका फ़ोटो जमा नहीं कर सके। ग़ौर तलब है कि इस पंचायत सहित बिहार के लाखों गांवों के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लिये दस हज़ार रुपये स्वयं ख़र्च कर शौचालय बना पाना एक सपने जैसा है। ज़ाहिर है जब इन्हें योजना के नियमानुसार शौचालय बनाने का पैसा नहीं मिल सकेगा तो खुले में शौच करने के सिवा इनके पास चारा ही क्या है ?

मज़े की बात तो यह है कि हिन्दू-मुस्लिम की संयुक्त आबादी वाले इस गांव में तथाकथित धर्मपरायण लोगों की भी बहुतायत है। दोनों समुदाय के लोग परस्पर प्रेम व सहयोग से रहते हैं। प्रायः मंदिरों में भजन और मस्जिदों से अज़ानों व मजलिस-मिलादों की आवाज़ें साथ साथ सुनाई देती हैं। पाप-पुण्य और स्वर्ग-नर्क के रास्ते भी यहाँ के धर्मगुरु अपने अनुयायियों को बख़ूबी बताते हैं। परन्तु कभी किसी मौलवी अथवा प्रवचन कर्ता को सफ़ाई पर 'प्रवचन ' देते कभी नहीं सुनियेगा। बल्कि यह लोग स्वयं इन्हीं गंदे व दुर्गन्धपूर्ण रास्तों पर राज़ी ख़ुशी चलते व इसी 'नरकीय वातावरण ' में रहते नज़र आयेंगे। मरणोपरांत लोगों को जन्नत भेजने का मार्ग बताने वाले प्रवचन कर्ता अपने अनुयायियों को नारकीय जीवन से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं बताते। यहाँ का आम आदमी चायख़ानों पर चाय व खैनी का आनंद लेता हुआ अमेरिका-ईरान-रूस-यूक्रेन जैसे जटिल अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बहस करता दिखाई देगा। यहाँ के लोग बी बी सी लंदन से कम किसी मीडिया हॉउस का समाचार सुनना पसंद नहीं करते। परन्तु इनकी यह 'तथाकथित जागरूकता' दशकों से इस ग्राम पंचायत में चली आ रही गंदिगी व दुर्गन्ध से मुक्ति पाने जैसे जीवन के सबसे ज़रूरी विषय को लेकर न जाने कहां चली जाती है। निश्चित रूप से ग्रामवासियों की इस तरह की अनदेखी ही सरकार व पंचायत के सच छुपाने के 'इश्तेहारी झूठ' को प्रोत्साहित करती है। (लेखक - निर्मल रानी / ईएमएस)

नव सम्वत् पर संस्कृति का सादर वन्दन करें

नवरात्र हवन के झोंके, सुरभित करते जनमन को।

है शक्तिपूत भारत, समरस हो जनमन में ?

नव सम्वत् पर संस्कृति का, सादर वन्दन करते हैं।

हो अमित ख्याति भारत की, हम अभिनन्दन करते हैं?

2 अप्रैल से विक्रम सम्वत् 2079 का प्रारम्भ हो गया है। विक्रम सम्वत् को नव संवत्सर भी कहा जाता है। संवत्सर पांच प्रकार के होते हैं, जिनमें सौर, चन्द्र, नक्षत्र, सावन और अधिमास सम्मिलित हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ एवं मीन नामक बारह राशियां सूर्य वर्ष के महीने हैं। सूर्य का वर्ष 365 दिन का होता है। इसका प्रारम्भ सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने से होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फाल्गुन

चन्द्र वर्ष के महीने हैं। चन्द्र वर्ष 355 दिन का होता है। इस प्रकार इन दोनों वर्षों में दस दिन का अंतर हो जाता है। चन्द्र माह के बढ़े हुए दिनों को ही अधिमास या मलमास कहा जाता है। नक्षत्र माह 27 दिन का होता है, जिन्हें अश्विन नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र कहा जाता है। सावन वर्ष में 360 दिन होते हैं। इसका एक महीना 30 दिन का होता है।

भारतीय संस्कृति में विक्रम सम्वत् का बहुत महत्त्व है। चैत्र का महीना भारतीय कैलेंडर के हिसाब से वर्ष का प्रथम महीना है। नवीन संवत्सर के संबंध में अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। वैदिक पुराण एवं शास्त्रों के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को आदिशक्ति प्रकट हुई थीं। आदिशक्ति के आदेश पर ब्रह्मा ने सृष्टि की प्रारम्भ की थी। इसीलिए इस दिन को अनादिकाल से नववर्ष के रूप में जाना जाता है। मान्यता यह भी है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इसी दिन सतयुग का प्रारम्भ हुआ था। मान्यता है कि इसी दिन सम्राट विक्रमादित्य ने अपना राज्य स्थापित किया था। श्रीराम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। नवरात्र भी इसी दिन से प्रारम्भ होते हैं। इसी तिथि को राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की थी। विजय को चिर स्थायी बनाने के लिए उन्होंने विक्रम सम्वत् का शुभारंभ किया था, तभी से विक्रम सम्वत् चली आ रही है। इसी दिन से महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीने और वर्ष की गणना करके पंचांग की रचना की थी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ऐतिहासिक महत्त्व भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की थी। इस दिन महर्षि गौतम जयंती मनाई जाती है। इस दिन संघ संस्थापक डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार का जन्मदिवस भी मनाया जाता है।

सृष्टि की सर्वाधिक उत्कृष्ट काल गणना का श्रीगणेश भारतीय ऋषियों ने अति प्राचीन काल से ही कर दिया था। तदनुसार हमारे सौरमंडल की आयु लगभग चार अरब 32 करोड़ वर्ष हैं। आधुनिक विज्ञान भी कार्बन डेटिंग और हॉफ लाइफ पीरियड की सहायता से इसे लगभग चार अरब वर्ष पुराना मान रहा है। इतना ही नहीं, श्रीमद्भागवद पुराण, श्री मारकंडेय पुराण और ब्रह्म पुराण के अनुसार अभिशेत् बाराह कल्प चल रहा है और एक कल्प में एक हजार चतुरयुग होते हैं। जिस दिन सृष्टि का प्रारम्भ हुआ, वह आज ही का पवित्र दिन था। इसी कारण मदुराई के परम पावन शक्तिपीठ मीनाक्षी देवी के मंदिर में चैत्र पर्व मनाने की परंपरा बन गई।

भारतीय महीनों का नामकरण भी बड़ा रोचक है अर्थात जिस महीने की पूर्णिमा जिस नक्षत्र में पड़ती है, उसी के नाम पर उस महीने का नामकरण किया गया है, उदाहरण के लिए इस महीने की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में हैं, इसलिए इसे चैत्र महीने का नाम दिया गया। क्रांति वृत पर 12 महीने की सीमाएं तय करने के लिए आकाश में 30-30 अंश के 12 भाग किए गए और उनके नाम भी तारा मंडलों की आकृतियों के आधार पर रखे गए। इस प्रकार बारह राशियां बनीं।

चूंकि सूर्य क्रांति मंडल के ठीक केंद्र में नहीं हैं, अतः कोणों के निकट धरती सूर्य की प्रदक्षिणा 28 दिन में कर लेती है और जब अधिक भाग वाले पक्ष में 32 दिन लगते हैं। इसलिए प्रति तीन वर्ष में एक मास अधिक हो जाता है।

भारतीय काल गणना इतनी वैज्ञानिक व्यवस्था है कि शताब्दियों तक एक क्षण का भी अंतर नहीं पड़ता, जबकि पश्चिमी काल गणना में वर्ष के 365.2422 दिन को 30 और 31 के हिसाब से 12 महीनों में विभक्त करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चार वर्ष में फरवरी महीने को लीप ईयर घोषित कर देते हैं। तब भी नौ मिनट 11 सेकेंड का समय बच जाता है, तो प्रत्येक चार सौ वर्षों में भी एक दिन बढ़ाना पड़ता है, तब भी पूर्णांकन नहीं हो पाता। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु घड़ी को एक सेकेंड स्लो कर दिया गया। फिर भी 22 सेकेंड का समय अधिक चल रहा है। यह पेरिस की वही प्रयोगशाला है, जहां के सीजीएस सिस्टम से संसार भर के सारे मानक तय किए जाते हैं। रोमन कैलेंडर में तो पहले 10 ही महीने होते थे। किंगनुमापाजुलियस ने 355 दिनों का ही वर्ष माना था, जिसे जुलियस सीजर ने 365 दिन घोषित कर दिया और उसी के नाम पर एक महीना जुलाई बनाया गया। उसके एक सौ वर्ष पश्चात किंग अगस्ट्स के नाम पर एक और महीना अगस्ट अर्थात अगस्त भी बढ़ाया गया। चूंकि ये दोनों राजा थे, इसलिए इनके नाम वाले महीनों के दिन 31 ही रखे गए। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी यह कितनी हास्यास्पद बात है कि लगातार दो महीने के दिनों की संख्या समान हैं, जबकि अन्य महीनों में ऐसा नहीं है। यही नहीं, जिसे हम अंग्रेजी कैलेंडर का नौवां महीना सितम्बर कहते हैं, दसवां महीना अक्टूबर कहते हैं, ग्यारहवां महीना नवम्बर और बारहवां महीना दिसम्बर हैं। इनके शब्दों के अर्थ भी लैटिन भाषा में 7,8,9 और 10 होते हैं। भाषा विज्ञानियों के अनुसार भारतीय काल गणना पूरे विश्व में व्याप्त थी और सचमुच सितम्बर का अर्थ सप्ताम्बर था, आकाश का सातवां भाग, उसी प्रकार अक्टूबर अष्टाम्बर, नवम्बर तो नवमअम्बर और दिसम्बर दशाम्बर है।

वर्ष 1608 में एक संवैधानिक परिवर्तन द्वारा एक जनवरी को नववर्ष घोषित किया गया। जेनदअवेस्ता के अनुसार धरती की आयु लगभग 12 हजार वर्ष है। चीनी कैलेंडर लगभग एक करोड़ वर्ष पुराना मानता है। चालडियन कैलेंडर धरती को लगभग दो करोड़ 15 लाख वर्ष पुराना मानता है। फीनीसयन इसे लगभग 30 हजार वर्ष की बताते हैं। सीसरो के अनुसार यह लगभग चार लाख 80 हजार वर्ष पुरानी है। सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमाणि आदि ग्रंथों में चैत्रशुक्ल प्रतिपदा रविवार का दिन ही सृष्टि का प्रथम दिन माना गया है।

संस्कृत के होरा शब्द से ही, अंग्रेजी का आवर (प्दल्ि) शब्द बना है। इस प्रकार यह सिद्ध हो रहा है कि वर्ष प्रतिपदा ही नववर्ष का प्रथम दिन है। एक जनवरी को नववर्ष मनाने वाले दोहरी भूल के शिकार होते हैं, क्योंकि भारत में जब 31 दिसम्बर की रात को 12 बजता है, तो ब्रिटेन में सायंकाल होता है, जो कि नववर्ष की पहली सुबह हो ही नहीं सकती। और जब उनका एक जनवरी का सूर्योदय होता है, तो यहां के ष्ज्ज्ब नै र्भ मनाने वाले रात्रि भर जागने कारण सो रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए सवेरे नहा धोकर भगवान सूर्य की पूजा करना तो अत्यंत दुष्कर कार्य है। परन्तु भारतीय नववर्ष में वातावरण अत्यंत मनोहारी रहता है। केवल मनुष्य ही नहीं, अपितु जड़ चेतना नर-नाग यक्ष रक्ष किन्नर-गंधर्व, पशु-पक्षी लता, पादप, नदी नद, देवी, देव, मानव से समष्टि तक सब प्रसन्न होकर उस परम शक्ति के स्वागत में सन्नध रहते हैं।

नववर्ष पर दिवस सुनहले, रात रूपहली, उषा सांझ की लाली छन-छन कर पत्तों में बनती हुई चांदनी जाली कितनी मनोहारी लगती है। शीतल मंद सुगंध पवन वातावरण में हवन की सुरभि कर देते हैं। ऐसे ही शुभ वातावरण में अखिल लोकनायक श्रीराम का अवतार होता है।

उल्लेखनीय है कि ज्योतिष विद्या में ग्रह, ऋतु, मास, तिथि एवं पक्ष आदि की गणना भी चैत्र प्रतिपदा से ही की जाती है। मान्यता है कि नव संवत्सर के दिन नीम की कोमल पत्तियों और पुष्पों का मिश्रण बनाकर उसमें काली मिर्च, नमक, हींग, मिश्री, जीरा और अजवाइन मिलाकर उसका सेवन करने से शरीर स्वस्थ रहता है। इस दिन आंवले का सेवन भी बहुत लाभदायक बताया गया है। माना जाता है कि आंवला नवमीं को जगत पिता ने सृष्टि पर पहला सृजन पौधे के रूप में किया था। यह पौधा आंवले का था। इस तिथि को पवित्र माना जाता है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना होती है।

निसंदेह, जब भारतीय नववर्ष का प्रारम्भ प्रारंभ होता है, तो चहुंओर प्रकृति चहक उठती है। भारत की बात ही निराली है।

कवि श्री जयशंकर प्रसाद के शब्दों में-

अरुण यह मधुमय देश हमारा
जहां पहुंच अनजान क्षितिज को
मिलता एक सहारा
अरुण यह मधुमय देश हमारा

इसमें संदेह नहीं कि आज हमारे दैनिक जीवन में अंग्रेजी कैलेंडर का बहुत प्रचलन है, परन्तु हमारे तीज-त्यौहार, व्रत, उपवास, रामनवमी जन्माष्टमी, गृह प्रवेश, विवाह तथा अन्य शुभ कार्यों के शुभमुहूर्त आदि सभी आयोजन भारतीय कैलेंडर अर्थात हिन्दू पंचांग के अनुसार ही देखे जाते हैं।

आइए इस शुभ अवसर पर हम भारत को पुनः जगतगुरु के पद पर आसीन करने में कृत संकल्प हों। (लेखक- उत्तर प्रदेश सरकार में हैप्पीनेस / अनुभूति पाठयक्रम के प्रभारी है।) (लेखक - डॉ. सौरभ मालवीय/ ईएमएस)

आज का इतिहास 2 अप्रैल

- 1671 अकबर द्वारा समाप्त किया गया जजिया कर औरंगजेब ने पुनः लागू किया.
- 1872 अमेरिकी आविष्कारक एफ.बी. मोर्स का निधन.
- 1915 स्विटरजरलैंड और इटली को जोड़ने वाली रेल सुरंग का उद्घाटन.
- 1933 क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी रणजीत सिंह का निधन.
- 1942 कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया.
- 1947 सुरक्षा परिषद ने जापान के कब्जे वाले प्रशांत सागर द्वीपों के लिए अमेरिका को न्यासी नियुक्त किया .
- 1961 फ्रांसीसी समुदाय के तहत मेडागास्कर स्वतंत्र हुआ.
- 1971 असम के भीतर ही मेघालय स्वायत्त पहाड़ी राज्य बना.
- 1996 रूस और बेलारूस ने राजनीतिक और आर्थिक सहयोग समझोता किया.
- 1998 कोंकण रेलमार्ग से हजरत निजामुद्दीन से तिरुवनंतपुरम तक राजधानी एक्सप्रेस की शुरुवात.

खेल - समाचार

महिला विश्व कप के खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराने उतरेगी इंग्लैंड : एक्लेस्टोन

क्राइस्टचर्च (ईएमएस)। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की महिला टीमें रविवार को यहां महिला विश्व कप के खिताबी मुकाबले में उतरेंगी। इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ने कहा है उनकी टीम अगर अपना सर्वश्रेष्ठ करे तो वह ऑस्ट्रेलियाई टीम पर जीत दर्ज कर सकती है। एक्लेस्टोन ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं जिससे वह उत्साहित हैं।

इस क्रिकेटर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराना एक अहम उपलब्धि होगी क्यांकि हाल में हुई एशेज सीरीज में इंग्लैंड की पुरुष टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस क्रिकेटर के अनुसार उनकी टीम अगर अच्छा प्रदर्शन करे तो किसी भी दिन निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है। इस बार हमारे पास एक अच्छा अवसर है। इंग्लैंड का विश्व कप से पहले प्रदर्शन काफी खराब रहा जिसमें टीम एशेज में अपनी विरोध टीम से हार गई थी। इसके बाद विश्व कप के शुरूआती मैच में भी उन्हें ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।

उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं कि अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलें और हमारे बल्लेबाज वैसी बल्लेबाजी करें जैसा वे कर सकते हैं और गेंदबाज भी वैसी गेंदबाजी करें जैसी वे कर सकते हैं तो हमारे पास जीत के लिए अच्छी टीम है।

ओसाका मियामी ओपन के फाइनल में पहुंची , मेदवेदेव हारे

मियामी गार्डन्स (ईएमएस)। जापान की नाओमी ओसाका मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में पहुंच गयी हैं। ओसाका ने महिला एकल के सेमीफाइनल मुकाबले में तीन सेट तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले के बाद 22वीं वरीय बेलिंडा बेनसिच को 4-6, 6-3, 6-4 से हराया। वहीं दूसरी ओर पुरुष एकल में रुस के दानिल मेदवेदेव क्वार्टर फाइनल में हारने के कारण नंबर एक रैंकिंग हासिल नहीं कर पाये। ह्यूबर्ट ने पुरुष वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मेदवेदेव को 7-6 (7), 6-3 से हराया। अब वह दूसरे नंबर पर ही रहेंगे।

महिला एकल में ओसका ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 के बाद पहली बार किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची हैं। अब खिताबी मुकाबले में ओसाका का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त इगा स्वियातेक से होगा। स्वियातेक ने एक अन्य सेमीफाइनल में 16वीं वरीय जेसिका पेगुला को 6-2, 7-5 से हराया था। स्वियातेक अब अगले सप्ताह जारी होने वाली रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की ऐश बार्टी की जगह शीर्ष पर पहुंच जाएगी क्योंकि बार्टी ने पहले ही खेल का अलविदा कह दिया था।

ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज नेविल ने खेल को अलविदा कहा

मेलबोर्न (ईएमएस)। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज पीटर नेविल ने खेल को अलविदा कह दिया है। नेविल इस साल फरवरी से ही खेल से दूर थे। कंधे की चोट के कारण न्यू साउथ वेल्स की ओर से उनका सत्र समय से पहले ही खत्म हो गया था। नेविल ने एक बयान में कहा, 'मुझे पहले ही अंदाजा था कि मैं अपने करियर के अंत के करीब हूं। यह मेरे लिए एक निराशाजनक सत्र था, मुझे लगता है कि मैंने अपने करियर के बाकी हिस्सों की तुलना में इस सीजन में चोट के कारण अधिक मैच गंवाए हैं। मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने में सक्षम था और मैं न्यू साउथ वेल्स के लिए इतने लंबे समय तक खेला।।'

नेविल ने साल 2015 एशेज में ऑस्ट्रेलिया की ओर शानदार प्रदर्शन करते हुए लॉर्ड्स में अपनी टीम की बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने इसके बाद आठ और टेस्ट मैच खेले। वह अंतिम बार नवंबर 2016 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होबार्ट में उतरे थे। ऑस्ट्रेलिया को उस टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से ही टीम में नेविल की जगह मैथ्यू वेड को शामिल कर लिया गया था। नेविल ने भले ही ऑस्ट्रेलिया की ओर से कभी एकदिवसीय क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन छोटे अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्हें नौ बार टी-20 टीम में रखा गया । नेविल ने कहा, 'मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं एक ऐसा शख्स था, जिसने खेल से बहुत कुछ सीखा। मैं भाग्यशाली रहा हूं कि मैं जितना हो सका उतने लंबे समय तक खेला।

आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने ब्रावो

मुम्बई (ईएमएस)। चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) टीम के अहम बल्लेबाज वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गये हैं। ब्रावो ने लखनऊ सुपरजाइंटस के दीपक हुड्डा का विकेट लेने के साथ ही यह रिकार्ड बनाया है। ब्रावो के अब आईपीएल में कुल मिलाकर 171 विकेट हो गये हैं। इस मामले में उन्होंने मुंबई इंडियंस के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ा है। गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी में भी ब्रावो ने अपने को साबित किया है। मुंबई के खिलाफ ब्रावों ने 139 की स्ट्राइक रेट से 304 रन बनाए हैं। इसके अलावा पंजाब और राजस्थान के खिलाफ भी 200 से अधिक रन बनाये हैं। ब्रावो के आईपीएल बल्लेबाजी करियर पर ध्यान दें तो उन्होंने 152 मैचों में 40 बार नाबाद रहते हुए 1537 रन बनाए हैं। उनकी औसत 22 तो स्ट्राइक रेट इस दौरान 130 रही है।

आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज इस प्रकार हैं :

ड्वेन ब्रावो 171 विकेट
लसिथ मलिंगा 170
अमित मिश्रा 166
पीयूष चावला 157
हरभजन सिंह 150

आजम ने 15 वां शतक लगाकर टीम को जीत दिनाने के साथ ही बनाया रिकार्ड

लाहौर (ईएमएस)। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने दूसरे एकदिवीसीय क्रिकेट मैच में अपनी टीम को जीत दिलाकर सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल की है। इस मैच में आजम ने इस दौरान अपने एकदिवसीय करियर का 15वां शतक लगाकर पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के 15 शतकों के रिकाड की बराबरी की है। सहवाग के अलावा श्रीलंका के उप्पल थरंगा और पाकिस्तान के मोहम्मद युसूफ ने भी इतने ही शतक लगाये हैं। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आठ विकेट पर 348 रन बनाये पर पाक टीम ने चार विकेट पर 349 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस सीरीज का पहला एकदिवसीय ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीता था। ऐसे में यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर आ गयी है।

इस मैच में बाबर ने कप्तान के तौर पर पाक की ओर से चौथा शतक लगाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड अजहर अली के नाम पर था जिन्होंने कप्तान के तौर पर तीन शतक लगाए थे। इस सूची में इजमाम उल हक 2, शाहिद अफरीदी 2, आमिर सोहेल, इमरान खान, रमीज राजा, सईद अनवर, शोएब मलिक 1-1 का नाम भी शामिल है।

पाकिस्तान की ओर से एकदिवसीय में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं।

20 सईद अनवर
15 बाबर आजम
15 मोहम्मद युसूफ
11 मोहम्मद हफीज
10 इजाज अहमद
9 इमाम उल हक
9 रमीज राजा

टी20 में सात हजार रन बनाने वाले भारत के छठे बल्लेबाज बने धोनी

नई दिल्ली (ईएमएस)। चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने आईपीएल के 15 वें सत्र में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में अपने सात हजार रन पूरे किये। धोनी टी20 प्रारुप में यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के धठे बल्लेबाज हैं। वहीं जहां तक विकेटकीपरों की बात है वह पहले भारतीय विकेटकीपर विकेटकीपर हैं। धोनी ने इसके अलावा इस मैच में छक्के से अपना खाता खोला। धोनी को यह रिकार्ड बनाने के लिए 16 रनों की ही जरुरत थी। सीएसके की पारी की अंतिम गेंद पर चौका लगाकर धोनी टी20 में सात हजार रन बनाने वाले भारत के छठे बल्लेबाज बने। इससे पहले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, शिखर धवन और रॉबिन उपथप्पा ने सात हजार का आंकड़ा हासिल किया है।

टी20 क्रिकेट में कोहली के नाम 10,326 रन दर्ज हैं जबकि रोहित ने अभी तक कुल 9,936 रन बनाए हैं। रैना ने 8654 जबकि धवन ने 8,818 रन बनाये हैं। उथप्पा ने टी20 में कुल 7,120 रन लिए हैं। विश्व भर के क्रिकेटरों की बात करें तो टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम है। गेल ने सबसे ज्यादा 14,562 रन बनाए हैं जबकि पाकिस्तान के शोएब मलिक 11698 रन के साथ दूसरे वहीं वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड 11430 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं।

धोनी ने सीएसके की ओर से 4687 जबकि राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स की ओर से 574 रन शामिल है। टीम इंडिया की ओर से खेलते हुए धोनी ने 1617 रन जुटाए हैं जबकि झारखंड की ओर से टी20 में उन्होंने 123 रन बनाए हैं।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार

मृदुता के साथ **दृढ़ता,** निर्मलता के साथ **निर्णायकता**

"ज़मीन से जुड़े और टेक्नोलॉजी के उपयोग की समझ रखने वाले भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात चौतरफा विकास करेगा"

मान्नीय मुख्यमंत्री

श्री भूपेन्द्रभाई पटेल के

नेतृत्व में

200

दिनों की जन सेवा की अथक परिश्रम यात्रा

मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने 200 दिनों में राज्य में 61 हजार किलोमीटर की यात्रा कर सघन लोक संपर्क किया, सरलता व सहजता से जनता के साथ चर्चा की, विभिन्न जन-हितकारी पहल को लागू किया और पूरे राज्य में विकास की एक नई लहर को शुरु करते हुए अपनी एक नई पहचान स्थापित की है

- गुजरात के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े 2 लाख 44 हजार करोड़ रुपए के बजट की प्रस्तुति

- 'एक हजार दिनों की देखभाल-स्वस्थ रहे माता और बाल', के मंत्र के साथ महिलाओं को पोषण युक्त आहार देने के लिए गुजरात सरकार 850 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 1000 दिनों तक गर्भवती महिला को पोषण युक्त आहार दिया जाएगा

- किसान भाइयों के हित में 'गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड' का गठन करके रसायन से युक्त खेती से मुक्ति। गुजरात का डांग 100% प्राकृतिक खेती वाला देश का पहला जिला बना

- मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजना द्वारा गौशाला, पांजरापोल और ट्रस्ट संचालित संस्थाओं का अवसंरचनात्मक विकास

- नल से जल कार्यक्रम के अंतर्गत तीव्र गति के साथ कार्यों को कार्यान्वित कर साल 2022 के अंत तक गुजरात को 100% नल से जल घोषित करने का संकल्प

गुजरात सरकार को सुप्रीम से झटका

साबरमती आश्रम पुनर्विकास योजना केस में तुषार गांधी की अर्ज़ी पर फिर होगी सुनवाई

गुजरात सरकार के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम २ सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करेंगे।

अहमदाबाद, ०१ अप्रैल। साबरमती में गांधी आश्रम की पुनर्विकास योजना मामले को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से खोला है। गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। योजना के खिलाफ महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी की याचिका पर फिर सुनवाई होगी। गुजरात हाईकोर्ट नए सिरे से इस पर सुनवाई करेगा। पुनर्विकास योजना के खिलाफ याचिका को खारिज करने के हाईकोर्ट के २०२१ के फैसले को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को मामले पर फिर से सुनवाई करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट गुजरात सरकार का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुनाए।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई कर बेंच ने कहा कि हमारा विचार है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार से हलफनामा भी नहीं मांगा, इसलिए इस मामले को फिर से खोला जाना चाहिए। हाईकोर्ट मामले की फिर से सुनवाई करे और पक्षों की बात सुने। हम इस मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट इस मामले की जल्द सुनवाई कर फैसला सुनाए। सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम २ सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करेंगे। गुजरात हाईकोर्ट से इस याचिका को फास्ट ट्रैक करने के लिए कहा जाना चाहिए। तब तक पुनर्विकास पर रोक लगनी चाहिए। तुषार मेहता ने कहा कि मैं लष्ट से इसे प्राथमिकता के आधार पर लेने का अनुरोध करूंगा। याचिकाकर्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि ट्रस्टियों को सुनने की जरूरत है क्योंकि मामला ट्रस्ट के जनादेश में आता है। गुण-दोष के आधार पर याचिका को संबोधित नहीं कर रहे हैं। आज के समय में महात्मा गांधी की विरासत को जीवित रखना ट्रस्ट का जनादेश है। गुजरात सरकार ने कहा कि सरकार ट्रस्टों की मौजूदगी के प्रति पूरी तरह सचेत है, लेकिन लष्ट को उस अनुरोध को सुनने दें। दरअसल गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग भी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया था।

तुषार गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने २५ नवंबर २०२१ को तुषार की याचिका खारिज कर दी थी। तुषार का कहना है कि उक्त परियोजना से साबरमती आश्रम की भौतिक संरचना बदल जाएगा और इसकी प्राचीन सादगी भ्रष्ट हो जाएगी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि २०१९ में गुजरात सरकार ने उक्तआश्रम को फिर से डिजाइन और पुनर्विकास करने के अपने इरादे को प्रचारित किया और दावा किया इसे "विश्व स्तरीय संग्रहालय" और "पर्यटन स्थल" के रूप में बनाया जाएगा। कथित तौर पर ४० से अधिक "सर्वागसम" इमारतों की पहचान की गई जिन्हें संरक्षित किया जाएगा जबकि बाकी लगभग २०० को ढहा दिया जाएगा। योजना में कैफे, पार्किंग स्थल, पार्क और साबरमती नदी की धारा के पुनरुद्धार जैसी सुविधाएं बनाने का दावा किया गया। याचिकाकर्ता को डर है कि उक्त परियोजना से साबरमती आश्रम की भौतिक संरचना बदल जाएगी और इसकी प्राचीन सादगी भ्रष्ट हो जाएगी, जो गांधीजी की विचारधारा को मूर्त रूप देती है और इसे व्यापक बनाती है। ये इन महत्वपूर्ण गांधीवादी सिद्धांतों के विपरीत है जो आश्रम का प्रतीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में लंबे समय तक रहे थे और यह देश के आजादी के आंदोलन से करीबी से जुड़ा रहा है।

गुजरात सरकार ५४ एकड़ में फैले इस आश्रम व इसके आसपास स्थित ४८ हेरिटेज प्रॉपर्टी को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। महात्मा गांधी के तीसरे पुत्र मनिलाल के अरुण गांधी के बेटे तुषार गांधी ने गुजरात सरकार की १२०० करोड़ रुपये की गांधी आश्रम मेमोरियल व प्रिसिंक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को चुनौती दी है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह राष्ट्रपिता की इच्छा व उनके दर्शन के खिलाफ है। गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में गुजरात सरकार साबरमती आश्रम की विभिन्न गतिविधियों की देखभाल करने वाले छह ट्रस्टों, गांधी स्मारक निधि नामक चेरिटेबल ट्रस्ट, अहमदाबाद नगर निगम तथा प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य सभी लोगों को प्रतिवादी बनाया गया था। लेखक व सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी ने इन ट्रस्टों से सवाल किया कि वे अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहे हैं?

उन्होंने कहा कि सरकार को इसमें दखलंदाजी की इजाजत नहीं देना चाहिए, क्योंकि गांधी स्मारक निधि का संविधान कहता है कि बापू आश्रम व स्मारकों को सरकार व राजनीतिक प्रभाव से दूर रखा जाना चाहिए। जब गांधी स्मारक बना था, तब सरकार से एक पैसा भी नहीं लिया गया था। बाद में संविधान में संशोधन कर इन स्मारकों की देखभाल के लिए सरकार से फंड लेने की इजाजत दी गई, लेकिन सरकार की भूमिका फंडिंग तक ही सीमित रखी गई, उसे अपने स्तर पर कोई कदम उठाने का अधिकार नहीं दिया गया।

जीएसटी की आय से छलका गुजरात सरकार का खजाना, अर्थव्यवस्था पटरी पर आने के संकेत

अहमदाबाद (ईएमएस) गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां ठप होने का राज्य में जीएसटी की आय पर गंभीर असर हुआ थाँ हालांकि वर्ष 2021-22 के वर्ष में जीएसटी की आय से गुजरात सरकार का खजाना छलक गया है, जो अर्थव्यवस्था के पुनः पटरी पर आने के संकेत दे रहा हैं जीएसटी के अमलीकरण के बाद गुजरात को वित्तीय वर्ष 2021-22 में सबसे अधिक आय हुई हैं बीते वित्त वर्ष में जीएसटी, वेट के अंतर्गत 86,780 करोड़ की आय हुई थी जिसमें मार्च महीने में जीएसटी के तहत रु. 4530 करोड़ की आय शामिल हैं जो गत मार्च 2021 की रु. 3523 करोड़ की आय के मुकाबले रु. 1007 करोड़ यानी 28.56 प्रतिशत अधिक हैं फरवरी 2022 की 4189 करोड़ के मुकाबले मार्च महीने में जीएसटी की आय 8 प्रतिशत अधिक हुई हैं गौरतलब है कि वर्ष 2020-21 में जीएसटी की रु. 66723 करोड़ की आय हुई थी जबकि वर्ष 2021-22 में रु. 86780 करोड़ की आय हुई हैं यानी 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में 20057 करोड़ रुपए अधिक आय हुई हैं कोरोना महामारी के चलते वर्ष 2020-21 में आर्थिक गतिविधियां ठप होने का असर जीएसटी की आय पर भी हुआ थाँ हालांकि वर्ष 2021-22 में जीएसटी की आय में वृद्धि गुजरात की अर्थव्यवस्था के पुनः पटरी पर लौटने का संकेत दे रही हैं वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसटी के तहत रु. 45464 करोड़ की आय हुई है जो वर्ष 2020-21 के रु. 30697 करोड़ की आय के मुकाबले रु. 14767 करोड़ या 48.10 प्रतिशत अधिक हैं गुजरात को वेट के तहत कुल रु. 30137 करोड़ रुपए की आय हुई थी, जो वर्ष 2020-21 के रु. 20827 करोड़ वेट कलेक्शन की तुलना में रु. 9310 करोड़ या 44.70 प्रतिशत ज्याद हैं

परेशानियों से हारती जिंदगी

गुजरात में ८८ दिनों में २०८ लोगों ने की आत्महत्या

सूरत, ०१ अप्रैल। सूरत में गुरुवार को आत्महत्या का प्रयास करने के ४ मामले सामने आए। ये मामले केवल १ घंटे में ही सामने आए। वहीं शहर में आत्महत्या के आंकड़ों की बात करें तो ये चौंकाने वाले हैं। पिछले ८८ दिनों में आत्महत्या के २०८ सामने सामने आए हैं। मतलब हर दिन औसतन दो से ज्यादा आत्महत्याओं के केस सामने आ रहे हैं। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं घरेलू कलह, कर्जा ना चुका पाना, बीमारी से परेशान और मानसिक रूप से प्रताड़ित लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वराछा में जहर पीकर आत्महत्या के अधिक मामले मिले तो पांडेसरा-लिंबायत और उधना में फांसी लगाकर आत्महत्या के अधिक मामले मिले हैं। जबकि सचिन जीआईडीसी और डिंडोली इलाकों में ट्रेन से कटने के केस अधिक हैं। जबकि रांदेर- सिंगणपोर औ डूमस में नदी में कूदकर आत्महत्या करने के केस अधिक मिल रहे हैं।

आत्महत्या के इन २०८ मामलों में १५८ पुरुष और ५० महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं में आत्महत्या के सबसे अधिक मामलों में घरेलू कलह कारण बना। ५० में से ४२ मामलों में महिलाओं ने घरेलू कलह के कारण आत्महत्या की।

जबकि ४३ पुरुषों ने कर्ज के तले दबे होने के कारण आत्महत्या की है। इसके अलावा २२ पुरुषों ने बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या की। १३ मामलों में प्रेम प्रसंग कारण बना। जबकि बेरोजगारी के चलते ३३ पुरुषों ने आत्महत्या की थी इसके अलावा ९ ऐसे भी मामलों में पुरुषों ने जिंदगी से परेशान होकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली थी और अपनी मौत के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराया था। इसके अलावा एक मामला मंगलवार को सामने आया जब सूरत बस डिपो के सामने एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, उसका शव पेड़ से लटका मिला। इस घटना के बाद वराछा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए स्मीमेर अस्पताल भेजकर जांच शुरू की। शव के पास से एक बैग मिला है। हालांकि पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। शहर में होने वाली आत्महत्या में सबसे ज्यादा फांसी लगाने के मामले हैं। कुल २०८ में १०८ मामले फांसी के हैं। इसके अलावा ४२ मामले जहर या एसिड पीकर आत्महत्या करने के १९ मामलों में ट्रेन के आगे कूदकर जान देने, २३ मामलों में पानी में डूबकर और १९ मामले बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने के हैं। पिछले ८८ दिनों में हुए २०८ आत्महत्या के मामले में ७६% पुरुष और २४% महिलाएं शामिल हैं।

जानकारी के मुताबिक साल २०२० की तुलना में साल २०२१ में आत्महत्या के केस ८ प्रतिशत तक बढ़े है। साल २०२० में जहां आत्महत्या के १,००६ मामले थे वहीं साल २०२१ में १०९० मामले मिले। वहीं साल २०१६ और २०२१ के आत्महत्या के केसों पर गौर करें तो २०१६ की अपेक्षा साल २०२१ में आत्महत्या के केस २१ प्रतिशत तक बढ़े हैं। साल २०१६ में आत्महत्या के ९०१ केस थे। वहीं साल २०२१ में १,०९० मामले आए।

कोरोना काल के बाद लोगों का स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ गया है। कोरोना से उद्योग-धंधों पर असर पड़ा है जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। पहले लोगों की सामाजिक समस्याएं बहुत होती थी। लेकिन कोरोना आने के बाद अब इसमें आर्थिक संकट भी जुड़ गया है। इससे लोगों का स्ट्रेस लेवल और बढ़ गया है। इसके अलावा लोगों में तुलना करने और प्रतिद्वंदी बनने की होड़ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है।

प्रदेश भर की आत्महत्या की बात करें तो साल २०१८ से ही सूरत में बाकी शहरों के मुकाबले सबसे अधिक केस मिले हैं। पूरे गुजरात में साल २०१९-२० में ७५०८ लोगों ने आत्महत्या की थी। वहीं साल २०१८-१९ में यह आंकड़ा ७५०५ था। प्रदेश के केवल ४ शहरों सूरत, अहमदाबाद, राजकोट और बड़ोदा में आत्महत्या करने के २,२८८ मामले पिछले साल सामने आए थे। जानकारी के मुताबिक साल २०१८ से २०२० तक सूरत में २,३५८ आत्महत्या हुई थीं। वहीं अहमदाबाद में २,२४०, राजकोट में १,२६२ और बडौदा में ७०७ मामले सामने आए हैं। सूरत में २०२१ में आत्महत्या के कुल १,०९० मामले सामने आए है। बुधवार दोपहर को १ घंटे में ही ४ लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। लिंबायत निवासी एक महिला ने पारिवारिक कलह से परेशान होकर चूहा मारने की दवा पी ली। वहीं एक युवक ने प्रेम प्रकरण में अपने हाथ की नसें काट लीं। जबकि आर्थिक तंगी से परेशान एक युवक फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। जबकि एक महिला ने जहर पी लिया।

पशु नियंत्रण विधेयक के खिलाफ पशु पालकों की बड़े आंदोलन की तैयारी

अहमदाबाद (ईएमएस) शहरों में आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के विरोध के बीच पशु नियंत्रण विधेयक पास कर दिया गया इस विधेयक का पशुपालक कड़ा विरोध कर रहे हैं और अब इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी हैं गौरतलब है कि पिछले काफी समय से राज्य में शहरों में आवारा पशुओं से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कई बार तो इन आवारा पशुओं के कारण लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी हैं स्थानीय प्रशासन से बार बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही थी आखिरकार सरकार ने इस दिशा में कदम उठाते हुए गुजरात विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन 31 मार्च को पशु नियंत्रण विधेयक पारित कर दिया विधानसभा में मंजूर हो चुका पशु नियंत्रण बिल जल्द कानून बनकर लागू हो जाएगा विधानसभा के इस विधेयक पास होने से पशुपालकों में आक्रोश है और उनकी मांग है कि पहले पशुओं के लिए उचित व्यवस्था करें ऐसा नहीं करने पर पशुपालकों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी हैं पशुपालक नेताओं का कहना है कि साधु-संतों के साथ हम चर्चा करेंगे और उनकी अगुवाई में अब गांधीनगर में 5 लाख जितने पशुपालकों का एकत्र कर सरकार के इस विधेयक का पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे पशु नियंत्रण विधेयक को लेकर कांग्रेस विधायक रघु देसाई ने कहा कि गुजरात में सबसे अधिक गौचर की जमीन भाजपा की सरकार के दौरान बेची गई हैं भाजपा केवल और केवल वोटों की राजनीति करती हैं भाजपा सरकार अब गायों को गौशालाओं में कैद कर देगी उन्होंने गायों के लिए शहर से बाहर व्यवस्था करने कीमांग की राज्य के पूर्व मंत्री भूपेन्द्रसिंह चूडास्मा ने विपक्ष पर प्रहार किया और कहा कि विपक्ष काफी खुश नजर आ रहा हैं उत्तर प्रदेश में 399 सीटों में से 387 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी हैं रफालेश्वर में गौमांस कांड कांग्रेस ने किया था आज कांग्रेस गाय को भी राजनीतिक नजरों से देख रही हैं उन्होंने गुजरात की भाजपा सरकार देशभर में सबसे पहले गौहत्या पर कानून लेकर आई थी

महंगाई का एक और झटका, अदानी ने सीएनजी की कीमतों में किया 5 रुपए का इजाफा

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात समेत देशभर में आज एलपीजी सिलिंडर की नई दरें प्रभावी हो गई हैं अब अदाणी गैस ने भी सीएनजी और कॉमर्शियल सिलिंडरों की कीमतों में इजाफा कर दिया हैं अदाणी गैस के प्रति किलो सीएनजी में 5 रुपए का इजाफा करने से नई दर रु. 79.59 हो गई हैं जबकि कॉमर्शियल एलपीजी में रु. 250 की वृद्धि के साथ इसके सिलिंडर की कीमत रु. 2253 पर पहुंच गई हैं पांच राज्यों के चुनावों के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं अब सीएनजी के कीमतों में वृद्धि की शुरुआत हो गई हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने का असर गुजरात समेत देश में दिखाई दे रहा हैं पहले पेट्रोल-डीजल और अब सीएनजी की कीमतें बढ़ने से वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं यह सिलसिला कब थमेगा यह कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि आगामी दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तेजी जारी रहेगी अहमदाबाद में पहले प्रति किलो सीएनजी की कीमत रु. 74.59 थी, जो रु. 5 की वृद्धि के साथ 79.59 पर पहुंच गई हैं वहीं वडोदरा में 5 रुपए के इजाफे के साथ प्रति किलो सीएनजी की कीमत रु. 76.84, पोरबंदर में रु. 82.59, खेडा में रु. 80.59, सुरेन्द्रनगर में रु. 80.59, नवसारी में रु. 80.59 हो गई हैं

सस्ता पेट्रोल-डीजल के लिए गुजरात आ रहे महाराष्ट्र के वाहन चालक

अहमदाबाद (ईएमएस) पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं और ऐसे में कहीं आधा पैसा सस्ता पेट्रोल मिलने की खबर मिलते ही वाहन चालक ईंधन भराने वहां पहुंच जाते हैं अगर प्रति लीटर पेट्रोल 14 रुपए और डीजल 4 रुपए सस्ता मिले तो लोगों की कतार लगना स्वाभाविक हैं दरअसल महाराष्ट्र के मुकाबले गुजरात में पेट्रोल और डीजल सस्ता हैं महाराष्ट्र से सटे गुजरात के एक पेट्रोल पंप पर इन दिनों वाहन चालकों की लंबी कतारें लग रही हैं महाराष्ट्र के मुंबई समेत अलग अलग जिलों में पेट्रोल-डीजल के दाम गुजरात से कहीं ज्यादा होने के कारण वहां के वाहन चालक वलसाड में ईंधन भरवाने आ रहे हैं महाराष्ट्र के पालघर, दहाणु, बोइसर, तलासरी और जवाहर के वाहन चालक सस्ता ईंधन पाने के लिए गुजरात का रुख कर रहे हैं दक्षिण गुजरात के वलसाड जिला स्थित पेट्रोल पंप महाराष्ट्र के पालघर से करीब 12 किलोमीटर दूर है, जहां मंगलवार को पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर रु. 99.74 और डीजल की रु. 94.09 थी जबकि सीएनजी प्रति किलो की कीमत रु. 71.84 थी जबकि उसी दिन पालघर में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत रु. 114.62 और डीजल रु. 97.38 में बिक रहा था प्रति लीटर अगर 4 से 14 रुपए ईंधन सस्ता मिल रहा है तो वाहन चालकों का उसकी ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक हैं गुजरात के बोर्डर क्षेत्र में कई पेट्रोल पंप मालिकों ने होर्डिंग्स लगा रखे हैं कि महाराष्ट्र के मुकाबले गुजरात में पेट्रोल-डीजल रु. 4 से रु. 14 तक सस्ता मिलेगा यही वजह है कि महाराष्ट्र से सटे वलसाड के पेट्रोल पंप पर महाराष्ट्र के वाहन चालकों की ईंधन भराने के लिए कतारें लगती हैं इतना ही नहीं महाराष्ट्र की ओर जानेवाले ज्यादातर ट्रक समेत अन्य वाहन वलसाड में टैंक फूल करवाने के बाद अपनी मंझिल की ओर बढ़ जाते हैं वलसाड जिले के तलवाडा गांव स्थित पेट्रोल पंप के मैनेजर रूपेश पटेल का कहना है कि गुजरात और महाराष्ट्र में पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों में बड़ा अंतर होने की वजह से बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के वाहन चालक यहां ईंधन भराना आते हैं यहां से एक किलोमीटर दूर ही महाराष्ट्र की सीमा हैं जिससे वलसाड से सटे महाराष्ट्र के जिलों के वाहन चालक यहां आकर पेट्रोल-डीजल और गैस भरवाकर लौट जाते हैं

विधानसभा चुनाव में अहम होगी ब्रह्म समाज की भूमिका : मालव पंडित

अहमदाबाद, 01 अप्रैल, 2022: श्री समस्त गुजरात ब्रह्मसमाज ने आज भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में ब्रह्म समाज के योगदान को बढ़ाने, समाज के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और समाज के लिए नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। समाज के युवा, उनका सशक्तिकरण।

समाज के विकास की प्रतीक्षा करने और युवाओं को मजबूत प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकप्रिय युवा मालवभाई पंडित को सभी गुजरात ब्रह्मसमाज के प्रदेश अध्यक्ष भरतभाई रावल और महासचिव अमितभाई दवे द्वारा प्रदेश युवा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

इस अवसर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मालवभाई पंडित ने कहा, ठब्रह्म समाज के कल्याण और उत्थान में योगदान देने के लिए मुझे जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। अपने स्वयं के समाज से संबंधित अन्य सामाजिक सेवा मामलों के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगारोन्मुखी योजनाओं को भविष्य में क्रियान्वित किया जाएगा। परशुराम दादा की साप्ताहिक आरती के साथ-साथ समस्त गुजरात ब्रह्म समाज राज्य स्तर की युवा शाखा द्वारा गांव-गांव युवा पदाधिकारियों की नियुक्ति।

उन्होंने बताया कि युवा शक्ति सम्मेलन की तरह सामाजिक एकता के लिए कार्य करने आएंगे। प्रमुख नेताओं ने बताया कि संगठन के ट्रस्टी श्री डॉ. यज्ञेशः आगामी घटनाओं पर डेव के साथ चर्चा की जाएगी

उल्लेखनीय है कि ब्रह्म समाज द्वारा नियमित आधार पर विभिन्न कल्याणकारी पहल की जाती हैं, जिसमें मुफ्त निदान शिविर, व्यापार शिखर सम्मेलन, ब्रह्म गौरव पुरस्कार और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। साथ ही परशुराम जयंती के अवसर पर 3 मई को टैगोर हॉल में भव्य डायरिया का आयोजन किया जा रहा है और अगले माह क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया जा रहा है

गुजरात में मंगलवार तक गरमी दिखाएगी कड़े तेवर, मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट

अहमदाबाद (ईएमएस) शहर समेत राज्यभर में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी हैं आगामी मंगलवार तक राज्य में भीषण गर्मी की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया हैं अहमदाबाद में गर्मी का पारा 41.9 डिग्री पर पहुंच गया जो 5 अप्रैल तक 43 डिग्री तक पहुंच सकता हैं अहमदाबाद समेत राज्यभर में गर्मी ने आज से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं मौसम विभाग के मुताबिक अगले पांच दिनों के दौरान उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्रऔर कच्छ में भीषण गर्मी को देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया हैं जिसके मुताबिक शनिवार को बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सुरेन्द्रनगर और कच्छ में यलो अलर्ट रहेगा रविवार को बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरकांठा, राजकोट, अमरेली, सुरेन्द्रनगर और कच्छ में यलो अलर्ट रहेगा सोमवार और मंगलवार को बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरकांठा में यलो अलर्ट रहेगा

दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों का अहमदाबाद में रोड शो आज

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल तेज हो रही हैं भाजपा और कांग्रेस पहले ही चुनावों को लेकर सक्रिय हो गई हैं और अब आम आदमी पार्टी (आप) अपना अभियान तेज करने जा रही हैं पंजाब चुनावों में शानदार सफलता से गदगद आप गुजरात चुनावों के लिए शनिवार को शंखनाद करने जा रही हैं आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अहमदाबाद में रोड शो का आयोजन किया गया हैं अरविंद केजरीवाल के दो दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं के आप में शामिल होने की संभावना हैं खबर है कि राजकोट कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक इंद्रनील राज्यगुरु आप में शामिल हो सकते हैं कल होनेवाले रोड शो के लिए अरविंद केजरीवाल आज देर रात तक अहमदाबाद पहुंच जाएंगे गुजरात दौरे के पहले अरविंद केजरीवाल तीन बैठकें करेंगे और उसके बाद शाम 4.30 बजे से शाम 6.30 बजे तक पूर्वी अहमदाबाद में रोड शो करेंगे इस रोड शो में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे 3 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे बाद में गुजरात आप के पदाधिकारी और कोर टीम के साथ केजरीवाल अलग अलग बैठकें करेंगे केजरीवाल की उपस्थिति में कांग्रेस के कई नेता आम आदमी पार्टी जॉइन कर सकते हैं

पश्चिम रेलवे चलायेगी बांद्रा टर्मिनस एवं अजमेर के बीच सुपरफास्टट स्पेशल ट्रेन

अहमदाबाद (ईएमएस) यात्रियों की सुविधा तथा उनकी मांग को पूरा करने के लिए तथा ग्रीष्म काल-2022 के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त संख्याा के मद्देनज़र पश्चिम रेलवे द्वारा मुंबई-अजमेर के बीच स्पे8शल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सुमित ठाकुर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ट्रेन का विवरण इस प्रकार हैः

? ट्रेन संख्या 09039/09040 बांद्रा टर्मिनस-अजमेर सुपरफास्ट स्पेशल (18 फेरे)

ट्रेन संख्या 09039 बांद्रा टर्मिनस-अजमेर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन प्रत्येपक बुधवार को बांद्रा टर्मिनस से 23.55 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 17.00 बजे अजमेर पहुंचेगी। यह ट्रेन 20 अप्रैल से 15 जून, 2022 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09040 अजमेर-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन प्रत्ये्क गुरुवार को अजमेर जं. से 23.45 बजे प्रस्थान् करेगी और अगले दिन 15.45 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 21 अप्रैल से 16 जून, 2022 तक चलेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा जं., अहमदाबाद जं., मेहसाणा, पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़ जं. और ब्यावर स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी 3 टियर एवं स्लीपर क्लास कोच होंगे। ट्रेन संख्या 09039 की बुकिंग 3 अप्रैल 2022 से यात्री आरक्षण केन्द्रों आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी ट्रेनों के परिचालन का समय, ठहराव और संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं

अहमदाबाद और कानपुर सेंट्रल के बीच चलेगी साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन

अहमदाबाद, रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की मांग व सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद और कानपुर सेंट्रल के बीच साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन विशेष किराए पर चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 01906/01905 अहमदाबाद-कानपुर सेंट्रल-अहमदाबाद समर स्पेशल (कुल 26 फेरे)

ट्रेन संख्या 01906 अहमबाद-कानपुर सेंट्रल स्पेशल दिनांक 5 अप्रैल 2022 से 28 जून 2022 तक प्रत्येक मंगलवार को अहमदाबाद से 15:05 बजे रवाना होकर अगले दिन 11:55 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी।इसी तरह ट्रेन संख्या 01905 कानपुर सेंट्रल-अहमदाबाद स्पेशल दिनांक 4 अप्रैल 2022 से 27 जून 2022 तक प्रत्येक सोमवार को कानपुर सेंट्रल से 15:35 बजे रवाना होकर अगले दिन 11:00 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में नडियाद, आणंद, छायापुरी, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना, रूपबास फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, टूंडला तथा इटावा स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्याप 01906 की बुकिंग 03 अप्रैल, 2022 से यात्री आरक्षण केन्द्रों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। उपरोक्तश ट्रेन विशेष किराये पर स्पे शल ट्रेन के रूप में चलेंगी। ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

चैत्र नवरात्रि के चलते आज से अंबाजी मंदिर में आरती और दर्शन के समय में बदलाव

बनासकांठा (ईएमएस) 2 अप्रैल, शनिवार से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और इस पवित्र पर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए अंबाजी आते हैं श्रद्धालुओं को अंबाजी मंदिर में आरती और दर्शन में कोई असुविधा ना हो इसके लिए विक्रम संवत के नए वर्ष से आरती दर्शन के समय में फेरबदल किया गया हैं नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना को समय भी तय कर दिया गया हैं नवरात्रि के पहले दिन यानी शनिवार से सुबर की आरती 7.30 से 7.30 बजे, सुबह 9.00 से 10.30 बजे घट स्थापना, 8.30 से 11.30 बजे तक दर्शन, दोपहर दर्शन 12.30 से 4.30 बजे तक, सायंकाल की आरती 7.00 बजे और 7 बजे से 9 बजे तक श्रद्धालु अंबाजी के दर्शन कर सकेंगे चैत्र की अष्टमी यानी 8 अप्रैल को सुबह 6 बजे आरती होगी और चैत्र पूर्णिमा 16 अप्रैल को सुबह की आरती भी 6 बजे होगी

पश्चिम रेलवे

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना क्र. एस/10/2022 दिनांक : 31.03.2022

अ.क्र.	आइटम का संक्षिप्त विवरण	मात्रा	टी.ओ.डी.
128	ब्रेक शूज	7706 नग	18-अप्रैल-22
129	मेन एलईडी सिग्नल लाइटिंग यूनिट-रेड, येलो और ग्रीन	922 नग	20-अप्रैल-22
130	हाई अवेलेबिलिटी सिंगल सेक्शन डिजीटल एक्सल काउंटर	6 सेट्स	21-अप्रैल-22
131	पॉवर केबल 2x25 एसक्यू एमएम	284 केएम.	22-अप्रैल-22
132	एलईडी सिग्नल लाइटिंग रूट, शंट एंड कॉलिंग ऑन	1058 नग	25-अप्रैल-22
133	हाई अवेलेबिलिटी सिंगल सेक्शन डिजीटल एक्सल काउंटर	26 सेट्स	25-अप्रैल-22
134	मोटर कॉन्टैक्टर	240 नग	28-अप्रैल-22
	रिवर्स नीलामी		
4	जेली फिल्ड क्वॉड केबल 6 क्वॉड 0.9 एमएम डाया	1500 केएम	11-अप्रैल-22

शुद्धिपत्र : 1) निविदा सूचना क्र. एस/07/2022 दि. 10.03.2022 में अ.क्र. 104 (हीटलेस रिजनरेटिव ट्विन टॉवर) हेतु निर्धारित तिथि को 02.04.2022 से स्थगित कर 11.04.202 कर दिया गया है.
विस्तृत निविदा सूचना ईएमडी, क्रय प्रतिबंध एवं विस्तृत निविदा शर्तों की जानकारी के लिये कृपया वेबसाइट www.ireps.gov.in तथा www.wr.indianrailways.gov.in का अवलोकन करें.

कृते प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक 0842

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस ⇌ अजमेर के बीच सुपरफास्ट विशेष ट्रेन चला रहा है

ट्रेन सं.	प्रारंभिक स्टेशन और गंतव्य	सेवा के दिन	प्रस्थान	आगमन
09039	बांद्रा (ट.) - अजमेर	20.04.2022 से 15.06.2022	23.55 बजे (बुधवार)	17.00 बजे (अगले दिन)
09040	अजमेर - बांद्रा (ट.)	21.04.2022 से 16.06.2022	23.45 बजे (गुरूवार)	15.45 बजे (अगले दिन)

ठहराव : बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा जं., अहमदाबाद जं., महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़ जं. और ब्यावर स्टेशन दोनों दिशाओं में।

संरचना: ऐसी 3-टियर, शयनयान श्रेणी कोच

विस्तृत जानकारी समय एवं ठहराव संबंधी जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in देखें

ट्रेन सं. 09039 की बुकिंग 03 अप्रैल 2022 सें पीआरएस काउंटरों एवं IRCTC की वेबसाइट पर खुलेगी | उपरोक्त ट्रेन विशेष किराये के साथ चलाई जायेगी |

पश्चिम रेलवे
www.wr.indianrailways.gov.in
हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly
हमें फॉलो करें : twitter.com/WesternRly

Azadi Ka Amrit Mahotsav

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ रखें

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादकः लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः कालीन E-mail : janhitaishi@yahoo.co.in फोन: 079-22921482 Mob.9375504122, 9327086467 R.N.I. 63177/95